MEDIA OWNERSHIP MONITOR INDIA

data LEADS

REPORTERS WITHOUT BORDERS
FOR FREEDOM OF INFORMATION

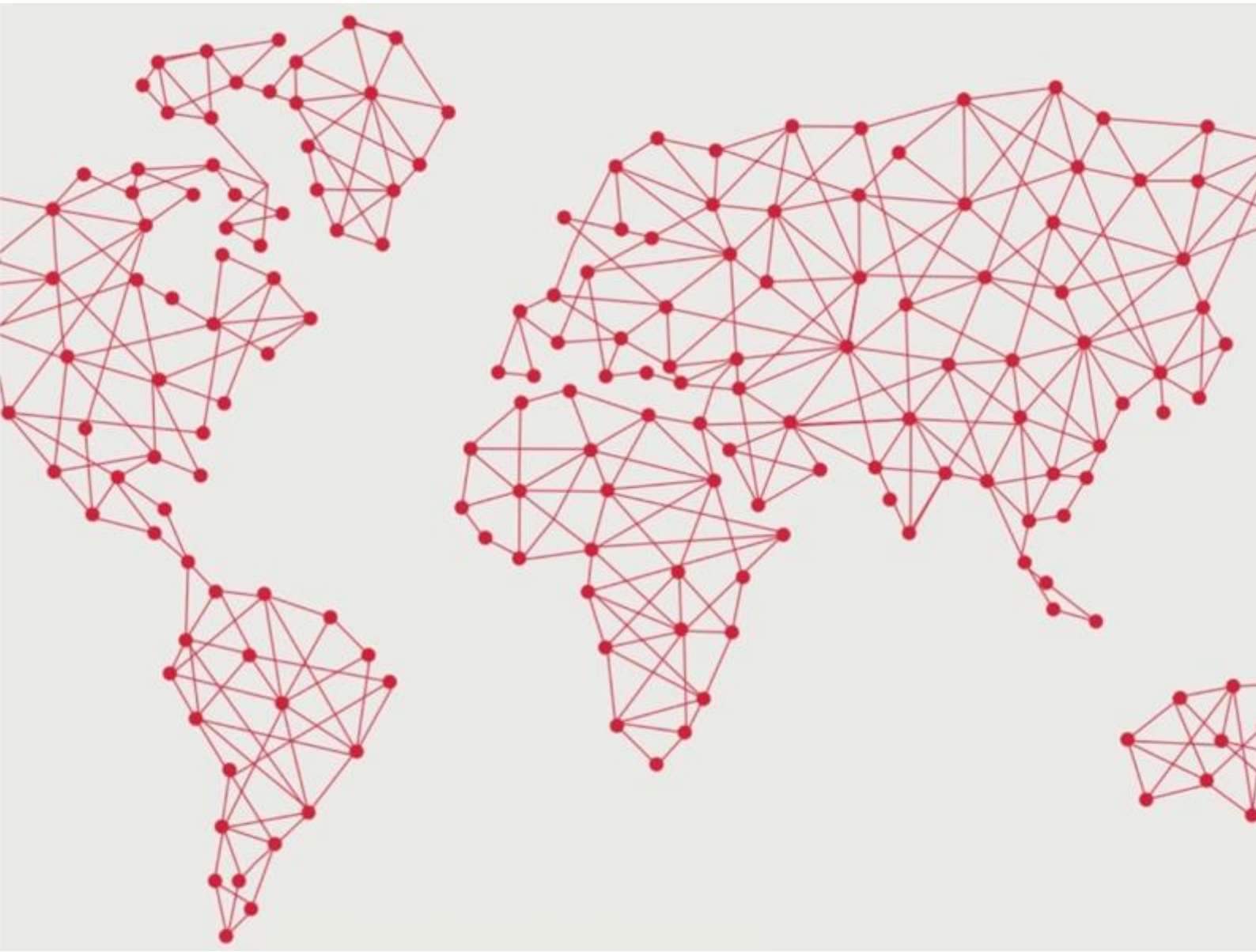

कानूनी आकलन

मीडिया ओनरशिप मॉनिटर के लिए प्रासंगिकता – भारत 2019

लेखक - निशा भंभानी

दिनांक: मई, 2019

रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF) संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को, के साथ परामर्शदात्री स्थिति वाला एक स्वतंत्र एनजीओ है। यूरोप काउंसिल और इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ फ्रैंकोफोनी (OIF)। इसके विदेशी खंड, इसके ब्यूरो मे ब्रसेल्स, वाशिंगटन, बर्लिन, ट्यूनिस, रियो डी जनेरियो और स्टॉकहोम और इसके नेटवर्क सहित दस शहर 130 देशों के संवाददाता RSF को समर्थन जुटाने, सरकारों को चुनौती देने और दोनों को प्रभावित करने की क्षमता देते हैं जमीन पर और मंत्रालयों और पूर्ववर्ती में जहां मीडिया और इंटरनेट मानकों और कानून का मसौदा तैयार किया गया है। जबसे 1994, बर्लिन में जर्मन अनुभाग सक्रिय है। हालांकि जर्मन खंड इंटरनेशनल के साथ मिलकर काम करता है पेरिस में सचिवालय दुनिया भर में मीडिया की स्वतंत्रता का अनुसंधान और मूल्यांकन करने के लिए, यह संगठनात्मक और वित्तीय रूप से है स्वतंत्र। उस भूमिका में, यह आर्थिक सहयोग के लिए संघीय जर्मन मंत्रालय में अनुदान के लिए आवेदन किया है और विकास - मीडिया स्वामित्व मॉनिटर परियोजना को वित्त करने के लिए।

डेटा लीड्स एक डेटा-संचालित भारतीय पहल है जिसका उद्देश्य डेटा रिसर्च और स्टोरीटेलिंग के नए प्लेटफॉर्म बनाना है। यह समर्पित है डेटा विज़ुअलाइज़ेशन और रिपोर्टिंग के रूप में विचारों और अंतर्दृष्टि को फैलाने के लिए। डेटा लीड्स OW डेटा लीड्स, a का एक हिस्सा है भारत में पंजीकृत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसकी स्थापना पुरस्कार विजेता भारतीय पत्रकार, मीडिया सैयद नजाकत ने की है ट्रेनर और उद्यमी।

संपर्क

नफीसा हसनोवा
वरिष्ठ परियोजना प्रबंधक आरएसएफ इंडिया
nh@reporter-ohne-grenzen.de
+32 488258553 (बेल्जियम)
+917303435774 (भारत)

सैयद नज़ाकत
संस्थापक और प्रधान संपादक
डेटा लीड्स
editor.dataleads@gmail.com
+919818395504

द्वारा वित्त पोषित

Federal Ministry
for Economic Cooperation
and Development

विषय-सूची

संक्षिप्त नाम....4

वैधीकरण....5

परिचय....6

1. **लीगल फ्रेमवर्क**....7
   - 1.1. मीडिया एकाग्रता....7
   - 1.2. मीडिया को रोकने / विनियमन से बाहर रखा गया है....7
   - 1.3. विधान पर्याप्त है?....7
   - 1.4. विधानों में मीडिया एकाग्रता की परिभाषा....8
   - 1.5. एकीकरण कार्यक्षेत्र एकीकरण....8
   - 1.6. विलय और अधिग्रहण....10
   - 1.7. विधान सभाओं में मीडिया व्यवसाय....11
   - 1.8. विदेशी निवेश....12

2. **कार्यान्वयन - नियंत्रण और मीडिया एकाग्रता की निगरानी....13**
   - 2.1. मीडिया एकाग्रता को शासित करती है....13
   - 2.2. प्राधिकारियों का अधिकार क्षेत्र....14
   - 2.3. प्राधिकारियों की स्वतंत्रता....14
   - 2.4. नियुक्ति प्रक्रिया....14
   - 2.5. बजट आवंटन....15
   - 2.6. प्राधिकारियों की शक्ति....16
   - 2.7. मीडिया एकाग्रता का आकलन करने की विधियाँ....16
   - 2.8. सार्वजनिक जवाबदेही....17
   - 2.9. सरकारी हस्तक्षेप....17
   - 2.10. विलय, अधिग्रहण और कार्यान्वयन....17
   - 2.11. पब्लिक इंटरेस्ट....17

3. **मीडिया स्वामित्व की पारदर्शिता....18**
   - 3.1. /2 मीडिया कंपनियों द्वारा प्रकटीकरण....18
   - 3.3. जानकारी जिसका का खुलासा करना आवश्यक है....19
   - 3.4. सूचना की पहुंच....21
   - 3.5. निगरानी और विनियमन....21
   - 3.6. पारदर्शिता....22

4. **अन्य राज्य मीडिया संगठनों पर प्रभाव डालते हैं....22**
   - 4.1. राज्य कर और प्रभाव....22
   - 4.2. प्रवेश बाधाएं....23
   - 4.3. मीडिया एकाग्रता और स्पेक्ट्रम आवंटन....24
   - 4.4. स्पेक्ट्रम आवंटन में पारदर्शिता....25
   - 4.5. राज्य विज्ञापन का वितरण....25
   - 4.6. राज्य विज्ञापन की निगरानी....27
   - 4.7. मीडिया व्यवसाय के साथ हस्तक्षेप करना....27
   - 4.8. कानून में संशोधन....29

5. **नेट तटस्थता....29**
   - 5.1. एनएन से संबंधित कानून....29
   - 5.2. एनएन से निपटने वाले कानून और प्राधिकरण....29
   - 5.3. एनएन की परिभाषा....29
   - 5.4. एनएन का कार्यान्वयन....29

6. **निष्कर्ष....30**
   - 6.1. स्रोत....31

Abbreviations (संक्षिप्त नाम)

Advertising Standards Council of India	ASCI
Broadcasting Content Complaints Council	BCCC
Broadcast Research Council of India	BARC
Community Radio Stations	CRS
Competition Commission of India	CCI
Digital Platform Owners	DPOs
Directorate of Advertising and Visual Policy	DAVP
Direct To Home	DTH
Department of Space	DoS
Department of Revenue	DoR
Department of Telecommunications	DoT
Electronic Media Monitoring Centre	EMMC
First Come First Serve	FCFS
Foreign Direct Investment	FDI
General Sales Tax	GST
Head-End-in the Sky	HITS
Indian Broadcasting Foundation	IBF
Inter-Ministerial Committee	IMC
Internet Protocol Television	IPTV
Indian Readership Survey	IRS
Local Cable Operator	LCO
Ministry of Corporate Affairs	MCA
Ministry of Home Affairs	MHA
Ministry of Information & Broadcasting	MIB
Multi System Operator	MSO
National Frequency Allocation Plan	NFAP
National Company Law Appellate Tribunal	NCLAT
Net Neutrality	NN
News Broadcasting Standards Authority	NBSA
News Broadcasters Association	NBA
Network Operation & Control Centre	NOCC
Over-The-Top Services	OTT
Press Council of India	PCI
Registrar of Newspaper	RNI
Registrar of Companies	ROC
Securities and Exchange Board of India	SEBI
Telecom Regulatory Authority of India	TRAI
Telecom Service Providers	TSPs
Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal	TDSAT
Television Audience Measurement	TAM
Traffic Management Practices	TMPs
Tax Deducted at Source	TDS
Television Rating Points System	TRPs
Wireless Coordination & Planning Wing	WPC

Legislations (वैधीकरण)

The Indian Telegraph Act, 1885

The Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (CTN Act)

The Cable Television Networks Rules, 1994 (CTN Rules)

The Competition Act of India, 2002

The Indian Penal Code, 1860 (IPC)

The Information and Technology Act, 2000 (IT Act)

Right to Information Act, 2005 (RTI Act)

The Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (TRAI Act)

The Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990

परिचय

सितंबर, 2018 की केपीएमजी रिपोर्ट ने अनुमान लगाया कि वित्तीय वर्ष 2023 में भारत में मीडिया उद्योग के 38.34 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद थी।[1]

मीडिया के एकाधिकार या मीडिया एकाग्रता के संबंध में भारत में स्थिति को "भारत में प्रमुख मीडिया कंपनियों की शक्ति का मानचित्रण" लेख में अच्छी तरह से अभिव्यक्त किया गया है, जहां यह इंगित किया गया था कि चूंकि मीडिया हमेशा सदस्यता राजस्व के बजाय विज्ञापन राजस्व पर निर्भर है। , इसने मालिकों को विज्ञापनदाताओं के अनुकूल मीडिया गुण बनाने में मदद की है और मीडिया को उन अधिकतम विज्ञापनों को प्राप्त होता है जो स्वामित्व एकाग्रता के लिए अग्रणी और अधिक मीडिया गुण पैदा करते रहते हैं। यह भी ध्यान दिया गया कि एक विज्ञापन संचालित कॉर्पोरेट मीडिया समाचार एक कॉर्पोरेट समूह द्वारा पेश किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं के लिए विपणन जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बन जाता है। ऐसा मीडिया अब तटस्थ मंच नहीं है, बल्कि एक सक्रिय एजेंट और औद्योगिक या राजनीतिक समूह का विस्तार है, जो "चौथे एस्टेट" और लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका के खिलाफ जा रहा है।[2]

इसलिए यह अनिवार्य है कि क्या भारत में मौजूद क़ानून और विधान मीडिया कंपनियों / उद्यमों / समूहों के स्वामित्व और नियंत्रण पैटर्न को नियंत्रित करने और मीडिया स्पेस में एकाधिकार और कुलीनवादी प्रवृत्ति को रोकने के लिए पर्याप्त हैं।

1. कानूनी ढांचा:

1.1 मीडिया की एकाग्रता को रोकने वाले कानून

मीडिया की सांद्रता से संबंधित विधान / कानून, चाहे भारत में क्रॉस मीडिया स्वामित्व, ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज एकीकरण खंडित हो और पूर्वोक्त शब्दों की मौजूदा विधानों में कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है.

मीडिया एकाग्रता और एकाधिकार को रोकने के लिए विधान / विनियम MIB द्वारा जारी दिशानिर्देशों, TRAI के विनियमों और 2002 के अधिनियम के प्रावधानों में पाए जा सकते हैं।

मीडिया एकाग्रता और एकाधिकार की रोकथाम के लिए बने कानूनों पर विस्तार से बताने से पहले, अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता की अवधारणा की प्रासंगिकता और महत्व का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है जो भारत में मीडिया / प्रेस को संविधान के तहत प्राप्त है।

(ए) मीडिया की सांद्रता को प्रभावित करने वाले सभी कानूनों / कानूनों के दायरे में भारत का संविधान है। यह सिद्धांत दस्तावेज है जिस पर सभी विधानों का परीक्षण किया जाता है। संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य घोषित करता है। संविधान के अनुच्छेद एक संकेतक हैं कि गतिविधि के सभी क्षेत्रों में बहुलता और विविधता को बनाए रखा जाना चाहिए।

(बी) संविधान अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत अपने नागरिकों को "बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता" प्रदान करता है जो स्वतंत्रता किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला है।

(सी) यद्यपि उक्त अनुच्छेद में विशेष रूप से प्रेस / मीडिया का उल्लेख नहीं है, वर्षों से भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय रहा है, ने स्वतंत्र भाषण के अधिकार की व्याख्या और पाठ किया है, जैसा कि कहा गया है कि अनुच्छेद में स्वतंत्र भाषण का अधिकार है प्रेस / मीडिया के रूप में अच्छी तरह से। सभी लोकतांत्रिक संगठनों की बुनियाद पर भाषण का 'प्रेस' / सूचना का प्रसार करने का मौलिक अधिकार प्रेस / मीडिया को स्पष्ट रूप से भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई मामलों में पसंद किया गया है जैसे कि रोमेश थापर वर्सस स्टेट ऑफ मद्रास[3] और बृज भूषण वर्सस स्टेट दिल्ली[4]।

(डी) प्रेस / मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध अनुच्छेद 19 (2) के तहत परिभाषित किए गए हैं, जो राज्य को स्वतंत्र भाषण पर उचित प्रतिबंध लगाने वाले कानून बनाने की अनुमति देता है, जहां इस तरह का कानून भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में है, सुरक्षा राज्य, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता या न्यायालय की अवमानना, मानहानि या अपराध के संबंध में।

(ई) उक्त अनुच्छेद में उल्लिखित प्रतिबंधों के अलावा, मीडिया को किसी अन्य के नीचे या किसी अन्य कारण से मुद्रण / प्रसारण से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। भारत में मीडिया के अधिकार न तो असीमित हैं और न ही अप्रतिबंधित हैं और नागरिकों की तुलना में स्वतंत्र भाषण के संबंध में मीडिया की कोई विशेष स्थिति नहीं है।

(एफ) "उचित प्रतिबंध" शब्द को विशेष रूप से संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में की है।

(जी) ऐसे कई उदाहरण भी आए हैं जब राज्य ने विभिन्न विधानों के माध्यम से स्वतंत्र भाषण के अधिकार को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया है, जिन कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दिया है। इस तरह के मामलों के संबंध में, कुछ महत्वपूर्ण मामले, इंटर आलिया, सकाल पेपर्स (पी)

[1] https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/in/pdf/2018/09/Media-ecosystems-The-walls-fall-down.pdf

[2] http://www.academia.edu/37877812/Mapping_the_Power_of_Major_Media_Companies_in_India

[3] AIR 1950 SC 594

[4] AIR 1950 SC 129

लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया[5], बेनेट कोलमैन एंड कंपनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया[6], टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सस महानगर टेलीफोन निगम[7] हिंदुस्तान टाइम्स वर्सेस स्टेट ऑफ यू.पी. और ओआरएस[8]। आदि जो मामलों ने न केवल प्रेस / मीडिया को अपने विचार, अपने पत्रकारों के विचारों को प्रकाशित करने के अधिकार को मान्यता दी, सामग्री और मात्रा के संदर्भ में संचलन का अधिकार प्रसारित होने पर भी 'व्यावसायिक भाषण' के रूप में मान्यता दी प्रेस और मीडिया की अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार।

(ए च) उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट बनाम राज नारायण और अन्य लोगों[9] ने भी "जनता को सूचना प्राप्त करने का अधिकार" को उक्त अनुच्छेद के एक हिस्से के रूप में मान्यता दी और कहा कि जनता को सूचना प्राप्त करने का अधिकार उतना ही महत्वपूर्ण और सूचना का प्रसार करने के लिए मीडिया के अधिकार के रूप में उसी कगार पर खड़ा था। 9 फरवरी, 1995 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, बंगाल[10] के वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ने निर्णय दिया कि 'एयरवेव या फ्रीक्वेंसी एक सार्वजनिक संपत्ति थी' जिसका अर्थ था कि राज्य प्रतिबंधों / शर्तों पर प्रतिबंध लगा सकता है। प्रसारण के लिए ऐसी आवृत्तियों का उपयोग करने वाली संस्थाओं / कंपनियों / व्यक्तियों को दी गई अनुमति / लाइसेंस के लिये।

(i) संविधान के अलावा, अन्य विधान / विनियम / दिशानिर्देश / नीतियां हैं जो मीडिया एकाग्रता / एकाधिकार को रोकने का प्रयास करते हैं, हालांकि 'एकाग्रता' की अवधारणा को मुख्य रूप से बाजार समूह में उद्यमों, कंपनियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने और बनाए रखने के संदर्भ में समझा जाता है।

(जे) मीडिया एकाधिकार को प्रभावित करने वाले विधान / विनियम / दिशानिर्देश / नीतियाँ हैं :

(i) एमआईटी द्वारा जारी डीटीएच दिशानिर्देश;
(ii) एमआईबी द्वारा जारी HITS प्रसारण सेवाएं प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश;
(iii) MIB द्वारा जारी भारत में IPTV का प्रावधान करने वाली दिशानिर्देश;
(iv) भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997;
(v) नियामक TRAI द्वारा जारी विनियम, टैरिफ आदेश और दिशा-निर्देश जैसे TRAI अधिनियम की खोज में इंटरकनेक्शन विनियम, सेवा विनियमों की गुणवत्ता, टैरिफ आदेश;
(vi) 25 जुलाई, 2011 को जारी निजी एजेंसियों (चरण- III) के माध्यम से एफएम रेडियो प्रसारण सेवाओं के विस्तार पर नीति दिशानिर्देश;
(vii) 2002 का अधिनियम;
(viii) कंपनी अधिनियम, 2013;
(ix) आयकर अधिनियम, 1961;
(x) आईपीसी;
(xi) आरटीआई अधिनियम;

1.2 मीडिया विनियमन से शामिल /बाहर रखा गया है

मोटे तौर पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक (टेलीविजन और रेडियो) उपरोक्त विधानों / विनियमों / दिशानिर्देशों / नीतियों द्वारा कवर किए जाएंगे क्योंकि मीडिया एकाधिकार को बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक तटस्थता पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में अनिवार्य रूप से समझा जाता है। ऐसे उद्देश्य के अनुरूप, सरकार की राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति का उद्देश्य सभी हितधारकों के बीच "प्रतिस्पर्धात्मक तटस्थता" प्रदान करके एक स्तरीय खेल मैदान स्थापित करने के लिए मौजूदा कृत्यों के विरोधी प्रतिस्पर्धा परिणामों को दूर करना है[11]। डिजिटल मीडिया आईटी अधिनियम, 2000 द्वारा विनियमित है, हालांकि इसके प्रावधान मीडिया एकाधिकार से नहीं निपटते हैं।

1.3 क्या विधान पर्याप्त है?

भारत में कई विधान, नियम, विनियम दिशानिर्देश और नीतियां संबंधित हैं, इतना है कि यह प्रतीत होता है कि यह एक 'विधायी देश से अधिक है। हालांकि, मीडिया एकाधिकार / एकाग्रता के क्षेत्र में, ये बहुत ही कानून और नियम काफी हद तक असंगत, व्यवस्थागत, अपर्याप्त और काफी हद तक अप्रभावी हैं।

(i) मीडिया एकाग्रता को रोकने के लिए कानून लाने के लिए अतीत में कई प्रयास हुए हैं।

(ए) ब्रॉडकास्टिंग बिल, 1997 और ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल, 2006 को प्रस्तावित किया गया था, लेकिन इसे कभी भी क़ानून / कानून में नहीं बदला गया। 1996 के विधेयक ने क्रॉस मीडिया स्वामित्व, विदेशी स्वामित्व का निषेध किया और प्रस्तावित किया कि किसी भी विज्ञापन एजेंसियों, राजनीतिक या धार्मिक निकायों और सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित निकायों को टेलीविजन चैनलों के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। इसने ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की भी मांग की। इसी तरह, 2006 के विधेयक ने मीडिया के विभिन्न क्षेत्रों में मीडिया समेकन और एकाधिकार को रोकने के लिए एक स्वतंत्र नियामक स्थापित करने और ब्याज के संचय पर प्रतिबंध लगाने की मांग की।

(बी) TRAI ने केबल सेवाओं में एकाधिकार और बाजार के प्रभुत्व से संबंधित नवंबर, 2013 में सिफारिशें दी थीं; हालांकि, MIB ने कहा कि ये सिफारिशें व्यवहार्य नहीं थीं, लागू करने के लिए

[5] AIR 1962 SC 305
[6] AIR 1973 SC 106
[7] AIR 1995 SC 2438
[8] 2003 (1) SC 591
[9] 2003 (1) SC 591
[10] 1995(2) SCC 161
[11] http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=79466

अव्यावहारिक थीं और इसलिए उन्हीं मुद्दों को CCI के लिए विचार के लिए संदर्भित किया गया था।[12]

(सी) TRAI ने 25 फरवरी 2009 को मीडिया स्वामित्व पर सिफारिशें भी जारी की थीं और 12 अगस्त 2014 को मीडिया स्वामित्व से संबंधित मुद्दे 'पर सिफारिशें जारी की थीं। जनवरी, 2019 तक, TRAI की सिफारिशें मीडिया स्वामित्व से संबंधित मुद्दे' 12 अगस्त 2014 से संबंधित हैं।, IMC द्वारा विचाराधीन है, जो MIB द्वारा स्थापित किया गया है, उसी की जांच के लिए। आईएमसी की दो बैठकें 23 फरवरी 2018 और 28 मार्च 2018 को आयोजित की गई हैं।[13]

1.4 विधानों में मीडिया एकाग्रता की परिभाषा

1. भारत में मौजूदा विधानों में मीडिया एकाग्रता की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है और न ही विशेष रूप से दर्शकों की हिस्सेदारी, परिसंचरण, बारी / अधिक / राजस्व, शेयर पूंजी या वोटिंग अधिकारों के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। मीडिया एकाग्रता को केवल प्रतिस्पर्धात्मक तटस्थता बनाए रखने और बाजार में प्रतिकूल प्रतिस्पर्धा को रोकने के संदर्भ में परिभाषित और समझा गया है। जबकि 2002 का अधिनियम इस पहलू से संबंधित है, TRAI के नियम और MIB दिशानिर्देश अनिवार्य रूप से "ऊर्ध्वाधर एकीकरण" को प्रभावित करते हैं।

(i) 2002 का अधिनियम बाजार में प्रतिकूल प्रतिस्पर्धा को रोकने का प्रयास करता है और जिससे मीडिया की एकाग्रता प्रभावित होती है। 2002 का अधिनियम कंपनियों / संस्थाओं की गतिविधियों के सभी क्षेत्रों पर लागू होता है, विशेष रूप से मीडिया के लिए नहीं। 2002 के अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि अधिनियम का उद्देश्य उन प्रथाओं को रोकना है जो प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अन्य प्रतिभागियों द्वारा व्यापार किया जाता है। भारत में बाजार[14] । इसके प्रावधान अनिवार्य रूप से प्रतिस्पर्धी-विरोधी समझौतों को रोकने के उद्देश्य से हैं, डोमिनेंट स्थिति का दुरुपयोग (पूर्व पद दोनों) और संयोजन (विलय, अधिग्रहण आदि) पर प्रतिकूल प्रभाव बाजार पर पड़ सकता है।

(ii) 2002 के अधिनियम के प्रारूपित होने से पहले, भारत में कानून लागू करने का एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 था, जो एकाधिकार को बनने से रोकने के लिए भी लागू किया गया था। 1969 के अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया क्योंकि यह अर्थव्यवस्था की वृद्धि के मद्देनजर पुरातन और शानदार पाया गया था।

(iii) एमआईबी ने एचएचएच, एचआईटीएस और आईपीटीवी से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए हैं जो मीडिया एकाग्रता विशेष रूप से ऊर्ध्वाधर एकीकरण को प्रभावित करते हैं लेकिन ये दिशानिर्देश ऊर्ध्वाधर एकीकरण को परिभाषित नहीं करते हैं।

(iv) क्षेत्रीय नियामक, TRAI ने अपने विनियम जारी किए हैं जो प्रसारकों और डीपीओ के बीच क्रमशः "प्रदान करना चाहिए" और "ले जाने" के गैर-भेदभावपूर्ण और गैर-विशिष्ट प्रावधानों को बढ़ावा देते हैं।

(v) "कंट्रोल' शब्द का अर्थ मीडिया एकाग्रता के संबंध में एक महत्वपूर्ण अवधारणा होनी चाहिए, क्योंकि एक मीडिया कंपनी दूसरे के नियंत्रण के साथ, चाहे ऊर्ध्वाधर एकीकरण या क्षैतिज एकीकरण से, इसका मतलब होगा कि सामग्री और संपादकीय नीतियों को नियंत्रित किया जा सकता है। इस शब्द में 2002 के अधिनियम में संदर्भ पाया गया है, धारा 5-नियंत्रण में एक या एक से अधिक उद्यमों द्वारा मामलों या प्रबंधन को नियंत्रित करना शामिल है, या तो संयुक्त रूप से या अकेले, दूसरे समूह या उद्यम पर; एक या एक से अधिक समूह, या तो संयुक्त रूप से या अकेले, दूसरे समूह या उद्यम पर; यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (27) में भी उल्लेख करता है, जहां यह कहा गया था कि "नियंत्रण" में निदेशकों के बहुमत को नियुक्त करने या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से कार्य करने वाले प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा। कॉन्सर्ट में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उनके शेयरहोल्डिंग या प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारकों के समझौतों या मतदान समझौतों या किसी अन्य तरीके से।

हालाँकि, ये परिभाषाएं मीडिया एकाग्रता को परिभाषित करने या इसे रोकने के लिए जरूरी नहीं हैं।

(vi) परिवार के सदस्यों को ब्याज नियमों के किसी भी संघर्ष में शामिल नहीं किया जाता है और न ही स्वामित्व की परिभाषा में उनकी संबद्धता को इस हद तक माना जाता है कि शेयरधारक पैटर्न, निदेशकों के नाम आदि को छोड़कर, कंपनी अधिनियम 2013 आदि जैसे विधानों द्वारा खुलासा किया जाना आवश्यक है।

1.5 वर्टिकल इंटीग्रेशन पर विधान

MIB और TRAI द्वारा जारी किए गए कानूनों, दिशानिर्देशों और विनियमों के अवलोकन पर, ऊर्ध्वाधर एकीकरण को प्रभावित करते हुए, यह स्पष्ट है कि ये कानून प्रसारण / दूरसंचार क्षेत्र में "नियंत्रण" वितरण / एकत्रीकरण के प्रयास में एकल व्यक्ति / कंपनी या समूह को ध्यान में रखते हैं।

(1) MIB ने DTH, HITS और IPTV से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए हैं जो मीडिया एकाग्रता विशेष रूप से ऊर्ध्वाधर एकीकरण को प्रभावित करते हैं। एमआईबी द्वारा जारी किए गए अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों के तहत अनुमतियाँ किसी भी टीवी चैनलों के संकेतों को किसी भी प्लेटफॉर्म पर ले जाने के लिए अनिवार्य हैं।

[12] https://main.trai.gov.in/sites/default/files/Recommendations__Cable_monopoly__final__261113%20(1).pdf

[13] https://www.televisionpost.com/mib-on-cross-media-restrictions-cable-monopoly-and-new-dth-guidelines/

[14] https://www.cci.gov.in/sites/default/files/cci_pdf/competitionact2012.pdf or the Bare Act titled The Competition Act, 2002.

DIB कंपनियों और HITS और IPTV कंपनियों के लाइसेंस पर MIB द्वारा प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसमें DTH कंपनी में प्रसारकों / केबल नेटवर्क कंपनी की हिस्सेदारी पर 20 प्रतिशत की कैप लगाई गई है और इसके विपरीत राष्ट्रीय सुरक्षा, नैतिकता और टेलीविजन सेवाओं के वितरण और प्रसारण में एकाधिकार इससे संबंधित चिंताओं का ध्यान रखना है[15] । दिशानिर्देश हालात:

प्रसारण कंपनियों और / या केबल नेटवर्क कंपनियों को लाइसेंस अवधि के दौरान किसी भी समय आवेदक कंपनी की कुल इक्विटी का 20% से अधिक का सामूहिक रूप से पात्र होने का पात्र नहीं होगा। इसी तरह, आवेदक कंपनी के पास प्रसारण और / या केबल नेटवर्क कंपनी में 20% से अधिक इक्विटी शेयर नहीं हो सकते।[16]

यह निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं में सार्वजनिक प्रसारक के साथ महत्वपूर्ण खेल की घटनाओं के संकेतों को साझा करना अनिवार्य है। स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल (प्रसार भारती अधिनियम के साथ अनिवार्य साझाकरण), 2007।

सार्वजनिक प्रसारक के चैनलों और संसद की ओर से संचालित चैनलों की अनिवार्य गाड़ी भी निर्धारित की गई है।

MIB द्वारा 25 जुलाई, 2011[17] को निजी एजेंसियों (चरण- III) के माध्यम से एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज के विस्तार पर नीतिगत दिशानिर्देश, जिन कंपनियों द्वारा अयोग्य घोषित किए गए हैं, अन्य कारणों के साथ, अनुमतियों के लिए आवेदन करने या बोली लगाने से- भारत में शामिल नहीं की गई कंपनियाँ, एक धार्मिक संस्था द्वारा नियंत्रित या उससे जुड़ी कंपनी; कंपनी द्वारा नियंत्रित या एक राजनीतिक संस्था के साथ जुड़े; कोई भी कंपनी जो एक विज्ञापन एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है या किसी विज्ञापन एजेंसी की सहयोगी है या किसी विज्ञापन एजेंसी या किसी विज्ञापन एजेंसी से जुड़े व्यक्ति द्वारा नियंत्रित है; एक ही शहर में किसी भी आवेदक की सहायक कंपनी; एक ही शहर में किसी भी आवेदक की होल्डिंग कंपनी; एक ही शहर में एक आवेदक के रूप में एक ही प्रबंधन के साथ कंपनियों; एक ही शहर में एक से अधिक इंटर-कनेक्टेड अंडरटेकिंग; एक कंपनी जो बोली प्रक्रिया या उसके होल्डिंग कंपनी या सहायक या एक ही प्रबंधन या एक परस्पर उपक्रम के साथ एक कंपनी में भाग लेने से डिबार कर दी गई है।

नीति दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 7 नीचे दिए गए हैं कई अनुमतियों के संबंध में प्रतिबंध जो कर सकते हैं एक शहर में अधिग्रहण किया जाना चाहिए और कहा कि हर आवेदक करेगा कुल के 40% से अधिक नहीं चलाने की अनुमति दी जाए शहर में चैनल न्यूनतम तीन के अधीन शहर में विभिन्न ऑपरेटरों और आगे के अधीन अनुच्छेद 8 में निहित प्रावधान। अनुच्छेद 8 के अनुच्छेद 8 नीति दिशानिर्देश राज्य की कोई इकाई अनुमति नहीं देगी देश में आवंटित सभी चैनलों के 15% से अधिक के लिए जम्मू और कश्मीर में स्थित चैनलों को छोड़कर, उत्तर पूर्वी राज्य और द्वीप प्रदेश। केवल शहर वार सीमाएँ जैसा कि नीति दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 7 में उल्लिखित है जम्मू और कश्मीर में स्थित चैनलों पर लागू होगा, उत्तर पूर्वी राज्य और द्वीप प्रदेश।

(2) जहाँ तक नियामक, TRAI का संबंध है, इसने कई विनियम और शुल्क आदेश जारी किए हैं जो एकीकरण एकीकरण को प्रभावित करते हैं:

एक समय में TRAI ने ऐसे विनियम लाए, जो हर ब्रॉडकास्टर द्वारा विभिन्न टेलीविज़न प्लेटफार्मों पर गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर संकेतों को 'प्रदान करना चाहिए' प्रदान करते हैं और जो प्रसारकों और प्रतिबंधित प्रसारकों के बीच वितरण समझौतों पर प्रतिबंध लगाते हैं, जो अन्य को रोकने वाले अनन्य व्यवस्था में प्रवेश करते हैं वितरण के लिए टेलीविजन चैनल प्राप्त करने से वितरक।

एमएसओ पर भी 'जरूर रखना' प्रावधान लगाया गया था

विनियम और टैरिफ आदेश जारी किए गए थे, जो उपभोक्ता की पसंद और उन चैनलों को चुनने की क्षमता की रक्षा करता था, जिन्हें वह देखना चाहता था और जिसमें यह अनिवार्य था कि प्रत्येक MSO / DTH / IPTV / HITS ऑपरेटर अपने ग्राहकों को एक एड्रेस सिस्टम का उपयोग करके प्रसारण सेवाएं प्रदान करता हो उपभोक्ताओं को एक ला-कार्टे आधार पर चैनल।

TRAI विनियमों ने हितधारकों के बीच एक गैर-भेदभावपूर्ण और गैर-विशिष्टता नीति को बढ़ावा दिया।

अंत में 2017 में, अपने सभी विनियमों और टैरिफ आदेशों को समेकित करने के लिए, TRAI ने टेलीकम्यूनिकेशन (ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल) सर्विसेज इंटरकनेक्शन (पता करने योग्य सिस्टम) विनियम, 2017 और टेलीकम्युनिकेशन (ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल) सर्विसेज (आठवां) (एड्रेसेबल सिस्टम्स) टैरिफ ऑर्डर लाया।, 2017 जिसने गैर-विभेदकारी और गैर-विशिष्ट प्रावधानों को जारी रखा, जिसे उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले चैनलों के "कार्ट" और "एला कार्टे" विकल्प प्रदान करने चाहिए। इन विनियमों और टैरिफ आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम इंडस डिपार्टमेंट ऑफ़ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन और अन्य के फैसले को बरकरार रखा गया था।[18]

2017 विनियम ऊर्ध्वाधर एकीकरण समझौतों को प्रभावित करते हैं, जिससे उपभोक्ताओं के लिए भेदभावपूर्ण वातावरण का

[15]https://mib.gov.in/sites/default/files/GuidelinesforDTHServiceDated15.3.2001.pdf

[16]https://mib.gov.in/sites/default/files/Detailsguidlinesupdated6.11.2007.pdf

[17]https://www.broadcastseva.gov.in/fm_Lading_Page/FM_Phase_III_Policy.pdf

[18]2019(2) SCC 104

निर्माण और अप्रत्यक्ष रूप से एकाधिकार को रोका जा सकता है।[19]

1.6 विलय और अधिग्रहण:

पिछले कुछ वर्षों में मीडिया कंपनियों के भीतर कई विलय और अधिग्रहण हुए हैं: [20]

समेकन और गठजोड़-

- 2010 में, सन नेटवर्क और नेटवर्क 18 ने "सन 18 मीडिया सर्विसेज" बनाने के लिए एक रणनीतिक गठबंधन में प्रवेश किया। Sun18 ने केबल, DTH, IPTV और HITS सहित सभी नेटवर्क के माध्यम से भारत में सभी प्लेटफार्मों पर 30 से अधिक चैनल वितरित किए।
- 2011 में, स्टार डेन मीडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और ज़ी टर्नर लिमिटेड ने संयुक्त रूप से टेलीविज़न सामग्री को संयुक्त और वितरित करने के लिए "प्रो मीडिया एंटरप्राइज" नामक एक 50:50 संयुक्त उद्यम का गठन किया।

इंट्रा- ग्रुप कॉर्पोरेट री-स्ट्रक्चरिंग:

- CCI ने वायरलेस ब्रॉडबैंड बिजनेस सर्विस (दिल्ली) प्राइवेट के विलय को मंजूरी दे दी। लिमिटेड (WBBS दिल्ली), वायरलेस ब्रॉडबैंड बिजनेस सर्विस (केरल) प्रा। लिमिटेड (WBBS केरल) और वायरलेस ब्रॉडबैंड बिजनेस सर्विस (हरियाणा) प्रा। लिमिटेड (WBBS हरियाणा) वायरलेस बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (WBSPL) में। इनमें से प्रत्येक पक्ष में 51 प्रतिशत और 49 प्रतिशत इक्विटी शेयर क्रमशः क्वालकॉम निगमित और भारती एयरटेल लिमिटेड के पास हैं।

अधिग्रहण –

- CCI ने IGH होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड के 27.5 प्रतिशत इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण को भी मंजूरी दी। लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड एक निजी कंपनी है और इंडिया टुडे ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है, जो टीवी और रेडियो, प्रिंट मीडिया, संगीत के प्रकाशन और वितरण आदि के माध्यम से प्रसारण में शामिल है। IGH भी एक निजी लिमिटेड कंपनी है और एक निवेश कंपनी है आदित्य बिड़ला समूह में, जिसमें दूरसंचार सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक हितों में विविधता है; आईटी और आईटी सक्षम सेवाएं आदि।

- रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा Network18 Group कंपनियों पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से इंटर-कनेक्टेड और इंटर-डिपेंडेंट अधिग्रहण की एक श्रृंखला से संबंधित स्वतंत्र मीडिया ट्रस्ट द्वारा एक नोटिस दायर किया गया था। आयोग ने 4 जी प्रौद्योगिकियों और ऐसी सेवाओं के माध्यम से सुलभ सामग्री का उपयोग करके टेलीविज़न चैनल, इवेंट मैनेजमेंट सेवाओं और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं की आपूर्ति के लिए व्यवसायों पर संयोजन के प्रभाव का आकलन किया। यह निष्कर्ष निकाला कि संयोजन प्रतियोगिता पर किसी भी सराहनीय प्रतिकूल प्रभाव को जन्म देने की संभावना नहीं थी और अधिग्रहण को मंजूरी दे दी गई थी।

- CCI ने निष्कर्ष निकाला कि RIL (Reliance India Limited) के पास था नेटवर्क 18 और टीवी 18 पर लक्षित कंपनियों और अप्रत्यक्ष नियंत्रण का अधिग्रहण किया, लेकिन यह भी कहा कि इस सौदे का प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आईएसपी की खुली पहुंच है, और नेटवर्क 18 समूह की संपत्ति इंटरनेट पर उपलब्ध है, जिसे उपभोक्ताओं द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। आईएसपीएल के अलावा इनफोटेल से भी।[21]

- डिज़नी ने पहली बार 2006 में UTV में 1.5 करोड़ की हिस्सेदारी हासिल की और 2011 तक उसने UTV में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 50.44 प्रतिशत कर ली, जिससे सह-संस्थापक रॉनी स्क्रूवाला और तीन अन्य की कंपनी में केवल 19.82 प्रतिशत हिस्सेदारी रह गई।

- डिज़नी ने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के साथ भी हाथ मिलाया और 2015 में एक स्पोर्ट्स चैनल लॉन्च किया।

- ज़ी ने दो बड़े ऑपरेशनल जनरल एंटरटेनमेंट चैनल-BIG मैजिक का अधिग्रहण किया, जो हिंदी बाजार और BIG गंगा के लिए एक कॉमेडी चैनल है, जो बिहार और झारखंड में एक लोकप्रिय भोजपुरी चैनल है।

- रिलायंस ने अपने टेलीविज़न प्रसारण व्यवसाय में अपनी 100 प्रतिशत हिस्सेदारी और रुपये के मूल्य के लिए सुभाष चंद्र के ज़ी समूह के लिए अपने रेडियो व्यवसाय में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी 1900 करोड़ रु का विभाजन किया।

[19]https://main.trai.gov.in/sites/default/files/Interconnection_Regulation_03_mar_2917.pdf
[20]http://www.oecd.org/daf/competition/TV-and-broadcasting2013.pdf
[21]https://www.medianama.com/2014/05/223-how-reliance-industries-acquired-network18-a-detailed-timeline-of-events/

- सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया ने ज़ी से टेन स्पोर्टस का अधिग्रहण किया

- ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन ने (अनिल अंबानी समूह) RBNL के रेडियो और टेलीविजन व्यवसाय का अधिग्रहण किया, जिससे BIG FM रेडियो चैनल में 49% हिस्सेदारी प्राप्त हुई, जबकि Zee एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड RBNL के टीवी व्यवसाय का मालिक होगा।

- डिश टीवी- वीडियोकॉन डी 2 विलय [22]

यह दिसंबर, 2018 तक ध्यान देने योग्य होगा, MIB द्वारा निजी उपग्रह टेलीविजन चैनलों को दी गई 883 अनुमतियों में से, 785 निजी उपग्रह टेलीविजन चैनलों को भारत से अपलिंक करने और भारत में डाउनलिंक करने की अनुमति है। 883 चैनलों में से 497 गैर-समाचार हैं और 386 समाचार चैनल हैं। हालांकि कई अच्छी तरह से स्थापित मीडिया कंपनियां थीं जिनके पास पहले से ही चैनल हैं और उन्हें नए चैनल चलाने की अनुमति दी गई थी, कुछ नई टीवी कंपनियों को भी चैनल अपलिंक करने की अनुमति दी गई थी।[23] फिर भी मीडिया के माहौल में काम करने वाली बड़ी और नामी कंपनियों की पकड़ और प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। 31 मार्च, 2018 को आरएनआई की वेबसाइट पर बताए अनुसार पंजीकृत प्रकाशनों की कुल संख्या 1,18,239 है, जिसमें समाचार पत्र 17,573 और आवधिक 100,666 हैं[24]।

मीडिया एकाग्रता से संबंधित कानून में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है।

1.7 विधानों में लैकुनस

1. विधानों में अंधे धब्बे मौजूद हैं क्योंकि ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज एकीकरण की कोई परिभाषा नहीं है और इसलिए पेड न्यूज की वृद्धि पर कोई नियंत्रण नहीं है; 'निजी संधि; 'निजी स्व-सेंसरशिप' मीडिया के विज्ञापन और निगमीकरण।

(i) मीडिया स्वामित्व का मुद्दा पहली बार 2009 में प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया द्वारा एक मसौदा रिपोर्ट में बताया गया था, जो कि MIB के इशारे पर आयोजित किया गया था। मसौदा रिपोर्ट में पाया गया कि क्रॉस मीडिया होल्डिंग्स और प्रासंगिक बाजारों में उच्च स्तर की एकाग्रता के अलावा, मीडिया उद्योग को ऊर्ध्वाधर एकीकरण की विशेषता भी थी।[25]

(ii) चूंकि उक्त मसौदा रिपोर्ट में मीडिया एकाग्रता, नियामक प्राधिकरण से संबंधित विधानों में अंधे धब्बे या लैकुना को इंगित किया गया था, TRAI 25 फरवरी, 2009 को जारी अपनी "मीडिया स्वामित्व की सिफारिशें" के साथ आया था, जिसमें यह स्पष्ट रूप से था कि

- क्षैतिज एकीकरण के संबंध में-बाजार की विफलता का कोई उभरता खतरा नहीं था
- कार्यक्षेत्र एकीकरण के संबंध में- प्रसारक को वितरण और इसके विपरीत में कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए।[26]

(iii) 2009 में उपरोक्त सिफारिशों के बाद, TRAI ने 12 अगस्त, 2014 को "मीडिया स्वामित्व से संबंधित मुद्दों" पर अपनी सिफारिशों में स्थिति और मुद्दों का फिर से विश्लेषण किया, जिसमें यह देखा गया कि पेड न्यूज की खराबी '; 'निजी संधि; 'निजी स्व-सेंसरशिप; विज्ञापन आदि, अप्रतिबंधित स्वामित्व और मीडिया के व्यावसायीकरण के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर फैल गए थे। संपादकीय रुख तय करने में केंद्रीय भूमिका लेने वाली मीडिया इकाई के व्यापारिक और विपणन प्रभागों के साथ, संपादकीय स्वतंत्रता का भी समझौता किया गया था। अप्रतिबंधित स्वामित्व ने समाचारों को रंग देने और सच्चाई को विकृत करने का नेतृत्व किया था।

मीडिया की एकाधिकार या मीडिया एकाग्रता की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं होने के मद्देनजर, 2014 की सिफारिशों में, TRAI ने "ऊर्ध्वाधर एकीकरण", "क्षैतिज एकीकरण" और "क्रॉस होल्डिंग कंट्रोल" शब्दों को समझने और स्पष्ट करने का प्रयास किया।

- "वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब एक सामान्य इकाई है, जो ब्रॉडकास्टर खुद हो सकता है या ब्रॉडकास्टर पर 'नियंत्रण' रखने वाला हितधारक हो सकता है, एक ही संबंधित बाजार में" डीपीओ "को नियंत्रित करता है और इसके विपरीत।"
- क्षैतिज एकीकरण का मतलब है कि एक आम इकाई, जो कि डीपीओ ही हो सकती है या डीपीओ पर 'नियंत्रण' रखने वाली हिस्सेदारी हो सकती है, संबंधित बाजार में डीपीओ की दो श्रेणियां" नियंत्रण "करती हैं।
- "क्रॉस-होल्डिंग का अर्थ है ऊर्ध्वाधर एकीकरण; क्षैतिज एकीकरण; अथवा दोनों"।

TRAI ने यह भी देखा कि समाचार और करंट अफेयर्स शैली अन्य शैलियों से ऊपर थी, जिसमें यह देखा गया था कि चूंकि समाचार शैली की बहुलता और दृष्टिकोण की विविधता पर सीधा प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसे उत्पाद बाजार के लिए प्रासंगिक

[22] https://economictimes.indiatimes.com/industry/media/entertainment/media/et-year-end-special-top- six-media-and-entertainment-deals-of-2016/articleshow/55807372.cms
[23] http://www.indiantelevision.com/regulators/ib-ministry/mib-gives-licences-to-5-new-channels-190119
[24] http://rni.nic.in/general/organisation-setup.aspx

[25] https://cablequest.org/pdfs/i_b/ASCI%20Cross%20Media%20ownership%20in%20India%202009.pdf
[26] https://main.trai.gov.in/sites/default/files/Recommendations_on_Media_Ownership.pdf

शैली माना जाना चाहिए। क्रॉस-मीडिया स्वामित्व नियमों[27] का निर्माण। जैसा कि ऊपर कहा गया है, मीडिया स्वामित्व से संबंधित 2014 की सिफारिशें आईसीसी को एमआईबी द्वारा संदर्भित की गई हैं। [28]

दिलचस्प रूप से TRAI ने भी एक प्रासंगिक टिप्पणी की कि मीडिया सामान्य वस्तुओं और सेवाओं के साथ ब्रैकेट नहीं किया जा सकता है और नहीं करना चाहिए। विचारों के लिए बाजार इससे बहुत अलग है, जैसे कि जूते या बिस्कुट। मीडिया एक उच्च उद्देश्य की सेवा करता है और अलग विचार की आवश्यकता है। प्रतियोगिता कानून में अपनाए गए सिद्धांत समाचार और विचारों की बहुलता की आवश्यकता को संबोधित करने के विशेष उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकते। जिससे अप्रत्यक्ष रूप से कहा जा सकता है कि मीडिया को 2002 के अधिनियम के दायरे में नहीं आना चाहिए।

2. TRAI की टिप्पणियों के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि मीडिया एकाग्रता से संबंधित कानून में अंधे स्पॉट न केवल विभिन्न शर्तों की विशिष्ट परिभाषाओं की कमी के कारण होते हैं, बल्कि मीडिया के एकाधिकार के विभिन्न पहलुओं से निपटने वाले विभिन्न विधियों और प्राधिकरणों के कारण भी होते हैं। / एकाग्रता जो मुद्दों की विभिन्न व्याख्याओं के साथ-साथ न्यायिक मुद्दों / विभिन्न प्राधिकरणों के बीच TRAI और सीसीआई के मामले में टकराव की ओर जाता है। यह टकराव स्पष्ट है और अंततः सुप्रीम कोर्ट द्वारा हल किया गया "CCI बनाम भारती एयरटेल लिमिटेड एंड ऑर।"[29] जिसमें अदालत द्वारा यह देखा गया था कि "चूंकि मामला दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित है जो विशेष रूप से TRAI अधिनियम द्वारा विनियमित है, संतुलन परमिट द्वारा बनाए रखा गया है। TRAI ने पहले ऐसे क्षेत्राधिकार से निपटने और निर्णय लेने का फैसला किया जो इसके द्वारा अधिक सक्षम रूप से संभाला जा सकता है। एक बार जब यह अभ्यास किया जाता है और TRAI द्वारा दिए गए निष्कर्ष होते हैं जो कि प्रथम दृष्टया निष्कर्ष का नेतृत्व करते हैं कि आईडीओ (इनकंबेंट डोमिनेंट ऑपरेटर्स) ने प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं में लिप्त हो गए हैं, सीसीआई को मापदंड द्वारा निर्धारित किए गए मामले की जांच के लिए सक्रिय किया जा सकता है प्रतियोगिता अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों में नीचे और इसे अपने तार्किक निष्कर्ष पर ले जाएं "।

3. यह ध्यान दिया जा सकता है कि प्रतियोगिता के टचस्टोन पर मीडिया के एकाधिकार के कारण अनिवार्य रूप से संघर्ष विधानों में या अधिकारियों के बीच उत्पन्न होते हैं। इस अवधारणा को त्रुटिपूर्ण माना जाता है क्योंकि प्रतियोगिता को समाचारों की बहुलता सुनिश्चित करने या मीडिया की एकाग्रता को रोकने के लिए आवश्यक नहीं है।

1.8 मीडिया व्यवसाय के भीतर विदेशी निवेश

जहां तक भारतीय मीडिया में विदेशी निवेश का संबंध है, निवेश से संबंधित क़ानून / नीतियां भारतीय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 2000 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति प्रभावी रूप अगस्त, 2017 हैं जो विभिन्न मीडिया क्षेत्रों में विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करते हैं। , साथ ही ऐसे निवेश किए जाने पर अनुपालन किया जाना चाहिए। दूरसंचार में 100% तक के विदेशी निवेश की अनुमति है। एफडीआई नीति में प्रसारण क्षेत्र में किए गए निवेश पर निर्देश और प्रतिबंध शामिल हैं, जिसमें प्रसारण सेवाएं (टेलीपोर्ट्स, डीटीएच सेवाएं, केबल नेटवर्क, मोबाइल टीवी, HITS) की स्थापना और प्रसारण सामग्री सेवाएं (स्थलीय प्रसारण एफएम) शामिल हैं। / एफएम रेडियो, 'न्यूज एंड करंट अफेयर्स' टीवी चैनल्स का अपलिंकिंग और नॉन-'न्यूज एंड करंट अफेयर्स 'टीवी चैनल्स / टीवी चैनल्स की डाउनलिंकिंग का अपलिंकिंग)। हालांकि, ऐसी कंपनियों में किए गए निवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जो ऑडियोविजुअल मीडिया, जैसे संगीत / सामग्री स्ट्रीमिंग सेवाओं के ऑनलाइन वितरण का कार्य करती हैं।

किसी भारतीय मीडिया कंपनी में विदेशी निवेश की अनुमति भारतीय विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड - (अनुमोदन मार्ग) या स्वतंत्र रूप से (स्वचालित मार्ग) से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद दी जाती है।[30]

(i) DTH, HITS, Teleports, Cable Networks (MSOs और LCOs) और मोबाइल टीवी में 100% तक FDI की अनुमति है जो अनिवार्य रूप से ऑटोमैटिक रूट के माध्यम से कैरिज प्रदाता को प्रसारित करते हैं।

(ii) समाचार सेवाओं और वर्तमान मामलों के चैनलों में कंटेंट सेवाओं के प्रसारण में विदेशी निवेश को 26% से बढ़ाकर 49% कर दिया गया है, हालांकि सरकार की अनुमति की आवश्यकता है।

(iii) स्वचालित मार्ग से सरकार की अनुमति के बिना समाचार और वर्तमान मामलों के चैनलों को जोड़ने में 100% तक की एफडीआई की अनुमति है।

(iv) स्थलीय एफएम रेडियो में विदेशी निवेश को 49% तक सीमित कर दिया गया है और सरकार की अनुमति की आवश्यकता है।

(iv) स्थलीय एफएम रेडियो में विदेशी निवेश को 49% तक सीमित कर दिया गया है और सरकार की अनुमति की आवश्यकता है।

[27] https://main.trai.gov.in/notifications/press-release/trai-issues-recommendations-issues-relating-media-ownership-1; https://main.trai.gov.in/sites/default/files/Recommendations_on_Media_Ownership.pdf

[28] ibid p.7

[29] 2019 (2) SCC 521

[30] https://dipp.gov.in/sites/default/files/CFPC_2017_FINAL_RELEASED_28.8.17.pdf

(vi) समाचार और समसामयिक मामलों से संबंधित प्रिंट मीडिया, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में एफडीआई की अनुमति 26% की सीमा तक है और निवेश के लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है।[31]

(vii) वैज्ञानिक / तकनीकी और विशेष पत्रिकाओं / पत्रिकाओं / जर्नल को प्रकाशित करने वाली भारतीय संस्थाओं में १००% एफडीआई की अनुमति दी गई है।

(ix) MIB ने FM रेडियो स्थलीय प्रसारण सेवाओं में 49% FDI (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) की अनुमति दी है

(x) फिल्म और विज्ञापन क्षेत्र दोनों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बिना किसी अन्य शर्त के स्वचालित मार्ग पर 100% तक स्वीकार्य है।

(ix) इसके अलावा एफडीआई नीति में 100% इक्विटी कैप और स्वचालित मार्ग की परिकल्पना की गई है, जहां यह ई-कॉमर्स से संबंधित है, जिसका अर्थ "डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर डिजिटल उत्पादों सहित वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री" है। कंप्यूटर, टेलीविज़न चैनल और किसी भी अन्य इंटरनेट एप्लिकेशन का नेटवर्क स्वचालित तरीके से उपयोग किया जाता है जैसे कि वेब पेज, एक्स्ट्रानेट, मोबाइल।

2. मीडिया एकाग्रता का कार्यान्वयन-नियंत्रण और निगरानी

2.1 मीडिया एकाग्रता को नियंत्रित करने वाले निकाय

1. 'मीडिया एकाग्रता' को संबोधित करने के लिए संस्थागत प्रणालियाँ हैं, लेकिन जैसा कि ऊपर दिए गए अनुभाग 1 में समझा गया है।

मीडिया सांद्रता से संबंधित विधानों / नियमों की भूलभुलैया को लागू करने और विनियमित करने वाले प्राधिकरण / संस्थान एमआईबी, TRAI और सीसीआई हैं।[32]

2. जबकि MIB ने इसके द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, जो DTH, HITS, IPTV, ब्रॉडकास्टिंग चॉइस और पॉलिसी में वर्टिकल इंटीग्रेशन विज़न से संबंधित हैं। FM रेडियो / CRS इत्यादि, TRAI से संबंधित इसके द्वारा जारी की गई दिशानिर्देश क्षेत्रीय नियामक ने प्रसारकों और डीपीओ के बीच ऊर्ध्वाधर एकीकरण को प्रभावित करने वाले नियम भी जारी किए हैं। CCI, दूसरी ओर बाजार नियामक डोमिनेंट स्थिति, संयोजन (विलय, अधिग्रहण समामेलन) और किसी भी अन्य विरोधी प्रतिस्पर्धा समझौते का दुरुपयोग करता है।

(ए) एमआईबी सार्वजनिक और निजी प्रसारण क्षेत्रों से संबंधित सभी नीतिगत मामलों के संबंध में केंद्र बिंदु है, चाहे रेडियो या टेलीविजन, और उक्त प्रसारण सेवाओं का प्रशासन और यह उपरोक्त क्षेत्रों की सभी सामग्री की निगरानी करता है।

(i) MIB को कार्यात्मक रूप से तीन पंखों में व्यवस्थित किया जाता है (i) सूचना विंग, (ii) ब्रॉडकास्टिंग विंग और (iii) फिल्म्स विंग जो MIB के पूर्वोक्त कार्यों को निष्पादित करते हैं।

(ii) निजी रेडियो चैनलों, एफएम चैनलों या सामुदायिक रेडियो के संबंध में, सामग्री को आकाशवाणी प्रसारण संहिता का पालन करना चाहिए। निजी रेडियो चैनलों के लिए, MIB अनुमतियाँ / लाइसेंस जारी करता है और नियामक प्राधिकरण TRAI है। सार्वजनिक प्रसारक, प्रसार भारती प्रसार भारती अधिनियम, 1990 के तहत स्थापित एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है, जो 23 नवंबर, 1997 को अस्तित्व में आया था। अखिल भारतीय रेडियो और प्रसार भारती अधिनियम, 1990 के संदर्भ में सार्वजनिक सेवा प्रसारण के उद्देश्य प्राप्त होते हैं। दूरदर्शन, जो पहले MIB के तहत मीडिया इकाइयों के रूप में काम कर रहा था और उपरोक्त तारीख से प्रसार भारती[33] के घटक बन गए। यह ध्यान रखना दिलचस्प होगा कि ऑल इंडिया रेडियो एक प्रमुख स्थान पर है जब रेडियो चैनलों पर समाचार प्रसारित करने की बात आती है क्योंकि निजी एफएम चैनल बड़े पैमाने पर मनोरंजन चैनल हैं।

(iii) यह केवल सीआरएस के मामले में है कि स्वामित्व से संबंधित कानून हैं, जिसमें सीआरएस से संबंधित नीति में कहा गया है कि सीआरएस के पास एक स्वामित्व और प्रबंधन संरचना होनी चाहिए जो उस समुदाय के प्रति चिंतनशील है जिसे सीआरएस सेवा देना चाहता है।[34]

(बी) जबकि एमआईबी अनुदान या प्रसारण की सामग्री की अनुमति देता है, चाहे टेलीविजन हो या रेडियो, यह TRAI है, जो सभी दूरसंचार सेवाओं के लिए नियामक प्राधिकरण है। TRAI अधिनियम, 1997 'प्रसारण सेवाओं' की धारा 2 (1) (के) के लिए 24 जनवरी 2000 को किए गए एक संशोधन द्वारा दूरसंचार सेवाओं की तह के भीतर लाया गया था।

(i) TRAI के पास TRAI अधिनियम, 1997 की धारा 11 (1) (ए) और (बी) के संदर्भ में सिफारिशी कार्य और अनिवार्य कार्य दोनों हैं। TRAI के कुछ अनिवार्य कार्यों में लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना, तकनीकी अनुकूलता सुनिश्चित करना और सेवा प्रदाताओं के बीच प्रभावी अंतर-संबंध सुनिश्चित करना, सेवा प्रदाताओं के बीच परस्पर संबंध की शर्तों को ठीक करना, राजस्व साझा करने के लिए सेवा प्रदाताओं के बीच व्यवस्था को विनियमित करना, बिछाने शामिल हैं। विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच दूरसंचार के स्थानीय और लंबी दूरी के सर्किट नीचे, इंटरकनेक्ट समझौतों के रजिस्टर को बनाए रखना, सबसे महत्वपूर्ण रूप से सेवा की गुणवत्ता बनाए रखना और

[31] https://mib.gov.in/sites/default/files/Guidelines_for_Publication_of_Indian_edition_of_Specialty_Magazines.pdf

[32] https://mib.gov.in.

[33] http://prasarbharati.gov.in/

[34] http://wdfindia.org/CRBGUIDELINES041206.pdf

सार्वभौमिक सेवा दायित्वों के साथ प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना।[35]

(c) बाजार नियामक, CCI दूसरी तरफ एक अलग क्षेत्र में काम करता है और इसके निर्णय काफी हद तक पूर्व के होते हैं। यह न तो कोई निकाय है जो लाइसेंस / अनुमति देता है और न ही यह एक नियामक निकाय है। वास्तव में, इसका ध्यान उद्यमों द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी लेनदेन पर निगरानी रखकर बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है और इसलिए यह कई कारकों पर विचार करता है और समझौतों को रोकने के लिए कार्य करता है जो प्रतिस्पर्धा-विरोधी हैं और जो बाजार की प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करते हैं।[36]

2002 का अधिनियम भारत में प्रासंगिक बाजार में एक उद्यम द्वारा प्राप्त ताकत की स्थिति के मामले में प्रमुख पद को परिभाषित करता है, जो इसे प्रासंगिक बाजार में प्रचलित प्रतिस्पर्धी बलों के स्वतंत्र रूप से संचालित करने में सक्षम बनाता है; या इसके प्रतिस्पर्धियों या उपभोक्ताओं या संबंधित बाजार पर इसके पक्ष में प्रभाव।[37]

CCI भी संबंधित बाजार[38] में प्रतिस्पर्धा पर संयोजन के सराहनीय प्रतिकूल प्रभाव का मूल्यांकन करता है जबकि पीसीआई एक वैधानिक निकाय है जो प्रेस काउंसिल एक्ट, 1978 के तहत प्रिंट मीडिया की निगरानी करता है, शासी वैधानिक प्रावधान मीडिया एकाधिकार से संबंधित नहीं हैं और न ही पीसीआई उपरोक्त से संबंधित है।.

(डी) सामग्री के विनियमन के लिए, एनबीएसए जैसे स्वतंत्र स्व नियामक प्राधिकरण हैं जो विज्ञापनों को विनियमित करने के लिए आईबीएफ और एएससीआई के सदस्यों के लिए सामान्य मनोरंजन चैनलों को विनियमित करने के लिए एनबीए, बीसीसीसी के सदस्यों के संबंध में 24*7 समाचार चैनलों को नियंत्रित करते हैं।

2.2 प्राधिकारियों का अधिकार क्षेत्र

(ए) उपरोक्त की एक व्याख्या लेने पर, यह ध्यान दिया जा सकता है कि एमआईबी, TRAI और सीसीआई को विभिन्न क्षेत्रों में संचालित करने का इरादा है और उनकी शक्तियों को सीटीएन अधिनियम 1995, सीटीएन नियम, 1994, एफएम रेडियो के लिए नीति दिशानिर्देशों के तहत अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। और TRAI अधिनियम, 1997 जो क्रमशः सामग्री और गाड़ी से संबंधित है और CCI के मामले में, यह 2002 के अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित है। जबकि MIB अनुमति / लाइसेंस जारी करता है, TRAI क्षेत्रीय नियामक है और मुद्दों के बाद सिफारिशें जारी करता है। हितधारकों द्वारा इनपुट पर विचार करना। सीसीआई, बाजार नियामक, दूसरी ओर, प्रतिस्पर्धी-विरोधी समझौतों, डोमिनेंट स्थिति का दुरुपयोग और संयोजन का बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हुए बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखने का प्रयास करता है।

(ख) हालांकि, दूरसंचार क्षेत्रीय नियामक, TRAI और बाजार नियामक, सीसीआई के बीच अधिकार क्षेत्र पर अतिव्यापी क्षेत्र के मुद्दे उठे हैं, दोनों प्रतियोगिता से संबंधित मुद्दों पर अधिकार क्षेत्र के अधिकार के लिए दावा करते हैं। CCI ने पहले आरोप लगाया है कि TRAI ने टैरिफ पर एक परामर्श पत्र के हिस्से के रूप में प्रभुत्व और शिकारी मूल्य निर्धारण के पहलुओं की जांच करके अपने अधिकार क्षेत्र को खत्म कर दिया था।

हालाँकि, इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर, 2018 को "सीसीआई बनाम भारती एयरटेल लिमिटेड और अन्य" शीर्षक से दिया गया था।[39]

2.3 प्राधिकारियों की स्वतंत्रता

TRAI और सीसीआई जैसे निकाय / प्राधिकरणों का निर्माण करने वाले क़ानून, इन निकायों को स्वतंत्र और किसी भी हस्तक्षेप या हस्तक्षेप, राजनीतिक या वाणिज्यिक से मुक्त बनाने का प्रयास करते हैं। इन निकायों में नियुक्तियां आमतौर पर कुछ क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाले व्यक्तियों की होती हैं और मौद्रिक आवश्यकताओं जैसे कि वेतन और अन्य खर्चों का ध्यान रखने के लिए क़ानून में प्रावधान है। बहरहाल, तथ्य यह है कि केंद्र सरकार नियुक्तियों में भूमिका निभाती है, कुछ सदस्यों को हटाने और इन प्राधिकरणों के बजट आवंटन। इसलिए, निकायों की पूर्ण स्वतंत्रता अभी भी उस सीमा तक बहस योग्य और अस्पष्ट है।

2.4 नियुक्ति प्रक्रिया

(1) दोनों वैधानिक निकायों के संबंध में, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं.

ए) TRAI अधिनियम के अनुसार, अध्यक्ष और TRAI के अन्य सदस्यों की नियुक्ति उन व्यक्तियों में से होती है, जिनके पास और दूरसंचार, उद्योग, वित्त, लेखा, कानून, प्रबंधन या उपभोक्ता मामलों में पेशेवर अनुभव का विशेष ज्ञान होता है। वे 3 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु तक सदस्य के मामले में और 70 अध्यक्ष के मामले में, जो भी पहले हो, के लिए पद धारण करते हैं। TRAI (संशोधन) अधिनियम, 2000 ने TRAI के पुनर्गठन का नेतृत्व किया था और वर्तमान में इसमें एक अध्यक्ष, दो पूर्णकालिक सदस्य और दो अंशकालिक सदस्य शामिल हैं। [40]

[35]https://main.trai.gov.in/sites/default/files/The_TRAI_Act_1997.pdf
[36]https://www.cci.gov.in/sites/default/files/presentation_document/anti_peter_20090213111438.pdf?download=1
[37]https://www.cci.gov.in/sites/default/files/advocacy_booklet_document/AOD.pdf
[38]https://www.cci.gov.in/sites/default/files/advocacy_booklet_document/combination.pdf
[39]Ibid p 10
[40]https://main.trai.gov.in/sites/default/files/The_TRAI_Act_1997.pdf

(बी) अपील प्राधिकारी जो विनियमों को चुनौती देता है (अधिनियम की धारा 36 के तहत विनियमों को चुनौती के अलावा) और TRAI के टैरिफ आदेश TDSAT है।

(सी) 2002 के अधिनियम में कहा गया है कि CCI में एक अध्यक्ष और दो से कम नहीं और 6 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, सभी को केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति के परामर्श से नियुक्त किया जाएगा जिसमें प्रमुख भी शामिल होंगे न्याय या उसका नामांकित व्यक्ति। अधिनियम में यह भी कहा गया है कि अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य क्षमता, अखंडता और खड़े होने वाले व्यक्ति होंगे और जिनके पास पंद्रह वर्षों से कम, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र, व्यापार, वाणिज्य, कानून का विशेष पेशेवर अनुभव नहीं होगा। , वित्त, लेखा, प्रबंधन, उद्योग, सार्वजनिक मामलों या प्रतियोगिता मामलों, प्रतियोगिता कानून और नीति सहित, जो केंद्र सरकार की राय में आयोग के लिए उपयोगी हो सकते हैं।[41] सर्वोच्च न्यायालय में एक संदर्भ और न्यायालय द्वारा की गई जांच के बाद अध्यक्ष / सदस्यों को केवल केंद्र सरकार द्वारा हटाया जा सकता है।

(डी) CCI के आदेशों / निर्णयों से अपील कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत गठित NCLAT को जाती है।

(ई) आईटी अधिनियम, २००० साइबर कानूनों से संबंधित है और यह हाल ही में अक्टूबर, 2000 में अस्तित्व में आया। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य आईटी नियम 2011 के तहत इंटरनेट पर सुलभ सामग्री के लिए निर्धारित कुछ मानकों को कानूनी मान्यता प्रदान करना था। आईटी अधिनियम के तहत साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण में एक अधिकारी से अपील की जाती है। 2017 में साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण को टीडीसैट के साथ उक्त निकाय के प्रभावी / गैर-कामकाज के कारण मिला दिया गया था।

(2) उपरोक्त प्राधिकारी निश्चित रूप से वैधानिक रूप से बनाए गए राजनीतिक स्वभाव और प्राधिकार नहीं हैं, जैसे कि टीडीसैट और एनसीएलएटी जैसे अपीलीय प्राधिकारी भी क़ानून द्वारा बनाए गए अर्ध-न्यायिक निकाय हैं। हालाँकि, कुछ निश्चित सीमाएँ हैं जो CCI और TRAI दोनों से ग्रस्त हैं;

(i) सीसीआई के सदस्यों का चयन एक चयन समिति के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है; हालाँकि, सरकार की नियुक्तियों पर अभी भी प्रभाव है। TRAI के मामले में, केंद्र सरकार सदस्यों की नियुक्ति करती है। इसलिए, सरकार के हस्तक्षेप की संभावना हमेशा बनी रहती है और सरकार द्वारा अपनी नीतियों के लिए सदस्यों को नियुक्ति की संभावना संभव है। इसलिए निकायों की पूर्ण स्वतंत्रता अस्पष्ट है;

(ii) सदस्यों का निष्कासन या निलंबन सरकार द्वारा CCI के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सहमति से किया जा सकता है, जो प्रक्रिया आसान नहीं है। हालाँकि, TRAI के मामले में, कुछ परिस्थितियों में सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा पद से हटाया जा सकता है;

(iii) CCI तकनीकी और प्रशासनिक मामलों से संबंधित नीति के प्रश्नों पर दिशा-निर्देशों से बंधा है, जैसा कि केंद्र सरकार समय-समय पर इसे लिखित रूप में दे सकती है। (iv) TRAI भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हितों में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश से बाध्य है और यह नीति के मामलों में भी केंद्र सरकार द्वारा निर्देशों से बाध्य है।

(v) CCI को केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम, 2002 में दिए गए कुछ कारणों से अलग किया जा सकता है, यदि सरकार का मानना है कि वह अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है या केंद्र सरकार आदि द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में चूक हुई है।

(vi) केंद्र सरकार, अधिनियम, 2002, किसी भी वर्ग के उद्यमों के आवेदन से छूट दे सकती है, यदि ऐसी छूट राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक हित में आवश्यक है।

(vii) TRAI के मामले में, यह अधिनियम में ही कहा गया है कि TRAI की सिफारिशें केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं हैं और इसलिए 2009 और 2014 में मीडिया स्वामित्व के संबंध में सिफारिशें जारी करने के बावजूद और सिफारिशें 2013 की इन सिफारिशों को केंद्र सरकार ने स्वीकार नहीं किया है और अभी भी अधर में लटकी है।

(viii) केंद्र सरकार द्वारा इन अधिकारियों को बजट आवंटित किया जाता है, लेकिन बजट आवंटित करते समय अधिकारियों से परामर्श नहीं किया जाता है और न ही उन्हें विश्वास में लिया जाता है।

(ix) दोनों निकायों / प्राधिकरणों के वार्षिक रिटर्न को केंद्र सरकार को भेजा जाना होता है.

2.5 अधिकारियों को बजट आवंटन

उपर्युक्त अधिकारियों के लिए बजटीय आवंटन उनकी वेबसाइट पर वार्षिक रिपोर्ट में देखे जा सकते हैं जो हर साल प्रकाशित होते हैं। [42]/[43] वास्तव में, TRAI और CCI दोनों अपने बजटीय वित्त के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर हैं।

TRAI के और सीसीआई के वार्षिक विवरण लेखा परीक्षा के अधीन होते हैं जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की मदद से किया जाता है, लेकिन रिटर्न और विवरण अभी भी केंद्र

[41] https://www.cci.gov.in/sites/default/files/cci_pdf/competitionact2012.pdf

[42] https://main.trai.gov.in/about-us/annual-reports

[43] https://www.cci.gov.in/annual-reports

सरकार को प्रस्तुत किए जाने हैं और दोनों निकाय अंततः उनकी गतिविधियों के लिए मंत्रालय को जवाबदेह हैं ।[44]

CCI और TRAI के मामले में, बजटीय भत्ते के लिए केंद्र सरकार पर वित्तीय निर्भरता है और केंद्र सरकार को धन आवंटन से पहले इन प्राधिकरणों से परामर्श करना भी अनिवार्य नहीं है;

हालांकि सीसीआई और TRAI द्वारा प्रयोग की जाने वाली निर्णय लेने की शक्ति सरकारी नियंत्रण से अपेक्षाकृत मुक्त है, हालांकि केंद्र सरकार पर वित्तीय निर्भरता का एक स्वाभाविक परिणाम इन अधिकारियों के स्वतंत्र कामकाज में बाधा के रूप में काम कर सकता है।

2.6 प्राधिकारियों की स्वीकृति शक्ति।

(i) जबकि MIB जैसे अधिकारियों के पास अनुमति जारी करने या नवीनीकरण करने या एक निश्चित अवधि के लिए चैनलों को बंद करने से इनकार करने की शक्ति है, यह आमतौर पर ऐसा तभी होता है जब अनुमति के नियमों और शर्तों का उल्लंघन होता है या जब सामान्य नियम और शर्तें होती हैं। अपलिंकिंग / डाउनलिंकिंग अनुमतियों का उल्लंघन किया जाता है जैसे कि कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता जैसे कि CTN अधिनियम, 1995 / CTN नियम, 1994 या सार्वजनिक हित, राष्ट्रीय सुरक्षा आदि के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। अनुमति रद्द करने के अन्य कारण जहाँ हैं, वहाँ हैं। चैनल के मालिक द्वारा रद्द करने के लिए अनुरोध किया गया है क्योंकि चैनल हवा में नहीं गया है / जब सुरक्षा मंजूरी से इनकार करने और / या आवश्यक अनुमति प्रस्तुत नहीं करने के कारण किसी चैनल को अनुमति नहीं दी गई है। मीडिया एकाग्रता या क्रॉस मीडिया स्वामित्व के आधार पर किसी भी अनुमति / लाइसेंस से इनकार नहीं किया गया है।

(ii) यह CCI है, जिसके पास प्रतिस्पर्धा-रोधी समझौते को संशोधित करने, बंद करने और अनुमति नहीं देने और उस संबंध में जुर्माना लगाने का अधिकार है।

(iii) क्रमशः TRAI या सीसीआई के नियमों / निर्णयों से अपील दायर करने के लिए टीडीसैट या एनसीएलएटीआर जैसे अपीलीय तंत्र पर्याप्त हैं। इन न्यायाधिकरणों के निर्णयों / आदेशों से भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाती है।

भारत में कानून के अनुसार, केंद्र सरकार इन निकायों या अपीलीय प्राधिकारियों के नियमों / निर्णयों को रद्द नहीं कर सकती क्योंकि वे वैधानिक निकाय हैं और अपीलीय अधिकारियों के निर्णयों / आदेशों से अंतिम अपील सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। यद्यपि सरकार के पास क्रमशः CCI या TRAI द्वारा जारी किए गए निर्णयों या सिफारिशों के संबंध में कोई भूमिका नहीं है, लेकिन यह हमेशा एक नया कानून लाने या संशोधन करने के माध्यम से कानून में संशोधन करके अधिकारियों के निर्णयों / आदेशों को बेअसर या बाधित कर सकता है। यह प्रक्रिया विशेष रूप से आसान नहीं है क्योंकि बाद के कानून भी चुनौती के लिए उत्तरदायी हैं।

2.7 मीडिया एकाग्रता का आकलन करने के तरीके

1. CCI के लिए, MIB और TRAI के लिए क्षैतिज एकीकरण और कंपनियों के ऊर्ध्वाधर एकीकरण का आकलन करने के तरीके अलग-अलग हैं। हालाँकि, उपरोक्त एकीकरण का आकलन करते समय निम्नलिखित सामान्य बातों पर ध्यान दिया जाता है:

- भुगतान की गई इक्विटी का प्रतिशत या कोई अन्य वित्तपोषण या वाणिज्यिक व्यवस्था है जो इसे वित्तीय, प्रबंधन या संपादकीय नीतियों पर प्रबंधन नियंत्रण दे सकती है;
- बाजार में नए प्रवेशकों के लिए बाधाओं का निर्माण;
- मौजूदा प्रतिस्पर्धियों को बाजार से बाहर निकालना;
- बाजार में प्रवेश में बाधा डालकर प्रतिस्पर्धा का सामना करना;
- उपभोक्ताओं को लाभ के लिए;
- माल के उत्पादन या वितरण या सेवाओं के प्रावधान में सुधार;
- माल के उत्पादन या सेवाओं के प्रावधान द्वारा तकनीकी, वैज्ञानिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना;
- बाजार में रिश्तेदार शेयर,
- उत्पादों या सेवाओं की प्रतिष्ठा;
- बाजार में हिस्सेदारी;
- उद्यम का आकार;
- प्रतियोगियों का आकार और महत्व;
- उद्यम की आर्थिक शक्ति
- निर्भरता; उपभोक्ताओं / दर्शकों पर
- ऐसे उद्यमों के उद्यमों या बिक्री या सेवा नेटवर्क का ऊर्ध्वाधर एकीकरण;
- एकाधिकार या प्रभावी स्थिति चाहे वह किसी भी क़ानून के परिणामस्वरूप प्राप्त की गई हो या सरकारी कंपनी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या अन्यथा होने के कारण;
- बाधाएं जैसे विनियामक बाधाएं, वित्तीय जोखिम, प्रवेश की उच्च पूंजी लागत, विपणन प्रविष्टि बाधाएं, तकनीकी प्रवेश बाधाएं, पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं, उपभोक्ताओं के लिए प्रतिस्थापन वस्तुओं या सेवा की उच्च लागत सहित बाधाएं;
- क्रय शक्ति का प्रतिकार करना;
- बाजार की संरचना और बाजार का आकार;
- सामाजिक दायित्व और सामाजिक लागत;
- आर्थिक विकास में योगदान के माध्यम से सापेक्ष लाभ, उद्यम द्वारा प्रतियोगिता में एक सराहनीय प्रतिकूल प्रभाव होने की संभावना या प्रमुख स्थिति का आनंद लेना;

[44] http://www.cuts-ccier.org/IICA/pdf/Country_Paper_India.pdf

- चैनलों या चैनलों के गुलदस्ते का शिकारी मूल्य निर्धारण.

2. 2002 के अधिनियम में, क्षैतिज एकीकरण का आकलन करने का तरीका कोई भी समझौता होगा जो:

- प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खरीद या बिक्री की कीमतें निर्धारित करता है;
- उत्पादन, आपूर्ति, बाजार, तकनीकी विकास, निवेश या सेवाओं के प्रावधान को सीमित या नियंत्रित करता है;
- बाजार के भौगोलिक क्षेत्र, या वस्तुओं या सेवाओं के प्रकार, या बाजार में ग्राहकों की संख्या या किसी अन्य तरह से आवंटन के माध्यम से बाजार या उत्पादन या सेवाओं के प्रावधान को साझा करता है;
- प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोली में हेराफेरी या मिलीभगत से बोली लगाने (बोलियों के लिए प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने या कम करने या बोली लगाने की प्रक्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित या हेरफेर करने का प्रभाव) होता है।
- एफएम रेडियो की नीति दिशानिर्देशों में, एक ही शहर में आवेदक के समान प्रबंधन वाली कंपनियां; एक ही शहर में एक से अधिक इंटर-कनेक्टेड अंडरटेकिंग एक अनुमति के लिए आवेदन करने के लिए अयोग्य हैं;

3. कार्यक्षेत्र समझौतों का मूल्यांकन इस प्रकार किया जाएगा:

(i) टाई-इन व्यवस्था (किसी भी सामान की खरीद के लिए किसी भी समझौते की आवश्यकता होती है, जिसमें ऐसी खरीद की शर्त के रूप में, कुछ अन्य सामान खरीदने के लिए);

(ii) विशिष्ट आपूर्ति समझौता (किसी भी मामले में खरीदार को अपने व्यापार के दौरान किसी भी मामले में प्रतिबंधित करने या विक्रेता से या किसी अन्य व्यक्ति के अलावा किसी भी सामान से निपटने में अन्यथा शामिल है);

(iii) विशेष वितरण समझौता (किसी भी सामान के उत्पादन या आपूर्ति को सीमित करने, सीमित करने या रोकने या माल के निपटान या बिक्री के लिए किसी क्षेत्र या बाजार को आवंटित करने के लिए कोई भी समझौता शामिल है);

(iv) सौदा करने से इनकार (इसमें कोई भी समझौता शामिल है जो प्रतिबंधित करता है, या प्रतिबंधित करने की संभावना है, किसी भी विधि द्वारा व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग जिन्हें माल बेचा जाता है या जिनसे सामान खरीदा जाता है);

(v) पुनर्विक्रय मूल्य अनुरक्षण (इस शर्त पर माल बेचने के लिए कोई समझौता शामिल है कि क्रेता द्वारा पुनर्विक्रय पर बदले जाने वाले मूल्य विक्रेता द्वारा निर्धारित मूल्य होंगे, जब तक कि यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जाता है कि उन मूल्यों से कम मूल्य वसूला जा सकता है) ।

MIB द्वारा DTH, HITS और IPTV को जारी किए गए लाइसेंस में प्रतिबंध या FM रेडियो से संबंधित पॉलिसी दिशानिर्देश किसी एक व्यक्ति, कंपनी या प्रमुख तत्व वितरण प्रक्रिया के समूह द्वारा चिंतन नियंत्रण करते हैं और उसी को मना करते हैं।[45] TRAI के विनियमों में टेलीविजन क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों के बीच गैर-भेदभावपूर्ण और गैर-विशिष्ट समझौतों की भी परिकल्पना की गई है।

2.8 सार्वजनिक जवाबदेही

सीसीआई के निर्णय / आदेश और TRAI की सिफारिशें और अपीलीय प्राधिकारी, एनसीएलटी और टीडीसैट के आदेशों को जनता उनकी वेबसाइट पर देख सकती है।

2.9 सरकार का हस्तक्षेप

जैसा कि पैरा 2.6 में कहा गया है, सरकार सीसीआई और TRAI के फैसलों को रद्द नहीं कर सकती है। हालांकि, यह किसी भी विनियमन या आदेश के प्रभावों को बेअसर करने के लिए एक नया कानून पेश कर सकती है।[46]

2.10 विलय, अधिग्रहण और कार्यान्वयन

पिछले पांच में कई विलय और अधिग्रहण हुए हैं, हालांकि उपरोक्त मामलों से संबंधित सभी समझौते सीसीआई से पहले नहीं हुए थे। जैसा कि ऊपर दिए गए पैराग्राफ 1.6 में उल्लेख किया गया है, मीडिया से संबंधित विलय / अधिग्रहण में से कोई भी सीसीआई द्वारा मीडिया स्पेस में बाजार की प्रतिस्पर्धा के लिए हानिकारक नहीं था और इसलिए अनुमोदित था। मीडिया की एकाग्रता को प्रभावित करने वाले विधानों के कार्यान्वयन में अधिकारियों के सामने मुख्य चुनौतियां यह हैं कि विभिन्न कंपनियों / उद्यमों के लेन-देन जटिल समझौतों और लेन-देन में समाहित किए जाते हैं जिससे इसे समझना मुश्किल हो जाता है।

इसके अलावा, चूंकि विधियां ओवरलैप होती हैं और किसी एकाधिकार को मापने के लिए याद्दाश्त की प्रतिस्पर्धा होती है, TRAI और सीसीआई दोनों कुछ सामान्य मामलों पर अधिकार क्षेत्र का दावा करते हैं।

2.11 जनहित

TRAI अधिनियम और 2002 के अधिनियम की प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि उक्त क़ानून विभिन्न कंपनियों, उद्यमों और समूहों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखने का प्रयास करके उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हैं। न तो निकाय को राजनीतिक या तकनीकी माना जाता है; इसलिए, यह माना जाता है कि दोनों निकाय उपभोक्ताओं / जनता के हितों में कार्य करेंगे, फिर भी नियुक्ति प्रक्रियाओं, निष्कासन प्रक्रियाओं और बजटीय आवंटन के मद्देनजर, निकाय पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं

[45] Ibid p.6/7/8
[46] Ibid. p.19

हो सकते हैं और इसमें संभावना हो सकती है कि अवसर आने पर उपभोक्ता हित से समझौता किया जा सकता है. [47]

जेक कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के मामले में बनाम सन डायरेक्ट लिमिटेड टीवी (पी) लिमिटेड (केस 8/2009) और डिश टीवी बनाम हैथवे एंड अदर्स (केस 78/2013) में, CCI ने क्रमशः 39 अगस्त, 2011 और 6 मई, 2014 को ऑर्डर दिए और उन्हें आयोजित किया डीटीएच द्वारा शिकारी मूल्य निर्धारण का अभ्यास एक प्रतिस्पर्धी प्रतिस्पर्धी एमएसओ नहीं था और एमएसओ द्वारा आरोप लगाया गया कि टीवी वितरण क्षेत्र में डीटीएच ने सामूहिक रूप से दुर्व्यवहार की स्थिति को गलत ठहराया था क्योंकि लेनदेन प्रतिस्पर्धा-विरोधी नहीं था।

समस्या यह तथ्य प्रतीत होता है कि प्रतिस्पर्धा की रक्षा के लिए प्रतिस्पर्धा कानून मौजूद है, न कि बहुलता। एक मीडिया बाजार में प्रतिस्पर्धा की उपस्थिति जरूरी नहीं है कि मीडिया स्वामित्व की बहुलता की उपस्थिति सुनिश्चित हो।

प्रतिस्पर्धा कानून सभी कंपनियों के लिए उदारतापूर्वक लागू होता है और विशेष रूप से मीडिया कंपनियों की अजीब स्थिति को संबोधित नहीं करता है।[48] इन मामलों में प्रतिस्पर्धा कानून लागू नहीं है क्योंकि यह एकल बाजार के भीतर एकाधिकार को रोकने का प्रयास करता है। उनकी परिभाषा के अनुसार, कई बाजारों में क्रॉस-मीडिया स्वामित्व और ऊर्ध्वाधर एकीकरण चिंता एकाधिकार है।[49]

वास्तव में, कारवां पत्रिका में किए गए एक लेख में, यह देखा गया था कि दूरसंचार क्षेत्र में डेटा योजनाओं के संबंध में सरकार द्वारा लिए गए कुछ निर्णय रिलायंस जियो को दूरसंचार क्षेत्र पर एकाधिकार बनाने में मदद कर रहे थे[50]। आरोप / अवलोकनों का खंडन किया गया।

3. मीडिया कंपनियों द्वारा मीडिया स्वामित्व

3.1 / 2 प्रकटीकरण की पारदर्शिता

मीडिया कंपनियों के स्वामित्व, निवेश और राजस्व स्रोतों के बारे में सूचना और पारदर्शिता के प्रकटीकरण के संबंध में, कंपनियों / उद्यमों के साथ काम करने वाला सामान्य कानून 2013 का कंपनी अधिनियम, सेबी विनियम और पुस्तकें अधिनियम का पंजीकरण है।

1. कंपनी अधिनियम, 2013 को इसके प्रावधानों के तहत कंपनियों द्वारा किए जाने वाले कुछ खुलासों की आवश्यकता है, जो अनिवार्य हैं:

(ए) उक्त अधिनियम की धारा 92 के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक कंपनी अपने शेयरों, डिबेंचर, अन्य प्रतिभूतियों और शेयरहोल्डिंग पैटर्न का खुलासा करते हुए निर्धारित प्रारूप में एक वार्षिक रिटर्न तैयार करे; विवरण, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से उनके नाम, पते, निगमन के देशों, पंजीकरण और पंजीकरण की हिस्सेदारी का संकेत देने वाले शेयरों के संबंध में; [51]

(बी) धारा ९ ३ में कहा गया है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी को आरओसी के साथ निर्धारित प्रपत्र में रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता है, इस तरह के बदलाव के पंद्रह दिनों के भीतर प्रमोटरों और ऐसी कंपनी के शीर्ष दस शेयरधारकों द्वारा रखे गए शेयरों की संख्या में परिवर्तन के संबंध में

(सी) धारा 129 के लिए कंपनी को वित्तीय विवरण दर्ज करने की आवश्यकता होती है जो कंपनी या कंपनियों के मामलों की स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देती है, धारा 133 के तहत अधिसूचित लेखा मानकों का अनुपालन करती है और उक्त बयानों को प्रपत्र में होना चाहिए अनुसूची III में विभिन्न वर्गों या कंपनियों के वर्गों के लिए दिए जा सकने वाले फॉर्म; कंपनियों को प्रमोटरों / प्रमोटर समूहों के लिए शेयरहोल्डिंग पैटर्न सहित शेयरहोल्डिंग पैटर्न का रिकॉर्ड बनाए रखना आवश्यक है; गैर प्रमोटर-गैर सार्वजनिक शेयरधारक और एक सार्वजनिक शेयरधारक का शेयरहोल्डिंग पैटर्न।

(डी) धारा 137 के लिए आवश्यक है कि वित्तीय विवरण की एक प्रति आरओसी के पास जमा की जाए, जिसमें समेकित वित्तीय विवरण, यदि कोई हो, के साथ सभी दस्तावेज जो ऐसे वित्तीय वक्तव्यों के साथ संलग्न किए जाने की आवश्यकता है, कंपनी की वार्षिक आम बैठक में विधिवत रूप से अपनाई जाए। इस तरह की फीस या अतिरिक्त शुल्क के साथ वार्षिक आम बैठक की तारीख के तीस दिनों के भीतर, जैसा कि धारा 403 के तहत निर्दिष्ट समय के भीतर निर्धारित किया जा सकता है।[52]

(ई) धारा 188 के लिए यह आवश्यक है कि किसी कंपनी के निदेशक मंडल की सहमति के लिए, किसी कंपनी के अनुबंध में शामिल होने या अन्य लेनदेन के लिए संबंधित पार्टी के साथ व्यवस्था करने के मामलों में, किसी भी संबंधित पार्टी की नियुक्ति की आवश्यकता होती है। कंपनी, उसकी सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी का कार्यालय या लाभ का स्थान। उक्त प्रावधान में शर्तें और छूट भी विस्तृत हैं। यह प्रावधान निजी और सार्वजनिक दोनों कंपनियों पर लागू होता है। संबंधित पक्ष की परिभाषा कंपनी

अधिनियम, 2013 की धारा 2 (76) के तहत पाई जा सकती है और यह संबंधित कंपनी, कंपनी के संदर्भ में बताती है:

(ए) एक फर्म, निजी कंपनी जिसमें भागीदार

[47] Ibid. pgs.17/18/19
[48] http://asu.thehoot.org/media-watch/law-and-policy/competition-vs-plurality-7718
[49] https://scroll.in/article/694139/five-reasons-why-media-monopolies-flourish-in-india
[50] https://caravanmagazine.in/reportage/government-helping-reliance-jio-monopolise-telecom
[51] http://www.mca.gov.in/SearchableActs/Section92.htm
[52] http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/CompaniesAct2013.pdf

(बी) निदेशक / प्रबंधक या उसका रिश्तेदार एक भागीदार या निदेशक या एक प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति या उनके रिश्तेदार या

(सी) एक निजी कंपनी या एक सार्वजनिक कंपनी जिसमें एक निदेशक या प्रबंधक एक निदेशक होता है और अपने रिश्तेदारों के साथ रखता है, इसकी पेड-अप शेयर पूंजी का 2% से अधिक होता है।

(एफ) आरओसी एमसीए के तहत काम करता है जो कि निकाय है जो कंपनियों के प्रशासन और सीमित देयता भागीदारी के साथ काम करता है। आरओसी सभी प्रमुख राज्यों में काम कर रहे हैं और केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में दोनों कंपनियों और एलएलपी को पंजीकृत करने के प्रमुख कर्तव्य के साथ काम कर रहे हैं।

मीडिया कंपनियों को आरओसी के साथ ऊपर उल्लिखित सभी खुलासों के साथ अपनी रिपोर्ट सालाना दर्ज करनी चाहिए।

2. दूसरी इकाई जिसे स्वामित्व आदि के संबंध में कंपनियों से खुलासे की आवश्यकता होती है, वह सेबी है जिसके लिए यह भी आवश्यक है कि जहां तक किसी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए रिपोर्टिंग की आवश्यकता है, इन कंपनियों को सूचीबद्ध प्रविष्टियों के लिए सेबी निरंतर प्रकटीकरण आवश्यकताओं के तहत आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। - भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विनियामक और प्रकटीकरण आवश्यकताओं की सूची) के विनियमन 30, विनियम, 2015 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) संशोधन नियम, 2018। 2015 के विनियमों की आवश्यकता है कि जब संयुक्त जैसे समझौतों उपक्रमों में प्रवेश किया जाता है, पार्टियों के नाम, शेयरहोल्डिंग, चाहे पक्ष प्रवर्तक / प्रवर्तक समूह की कंपनियों से संबंधित हों आदि का खुलासा किया जाना चाहिए। एक्सचेंजों के साथ-साथ वार्षिक रिपोर्ट दाखिल करना आवश्यक है।[53] प्रमोटर / प्रमोटर समूह द्वारा महत्वपूर्ण शेयरहोल्डिंग के साथ, अधिकांश भारतीय सूचीबद्ध इकाइयाँ प्रमोटर से प्रेरित हैं। तदनुसार, सूचीबद्ध संस्थाओं और प्रवर्तकों / महत्वपूर्ण शेयरधारकों के बीच बातचीत और संबंधों पर जाँच और संतुलन सुशासन के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए, 2018 संशोधन भौतिकता सीमा और साथ ही कार्यकारी / गैर-कार्यकारी निदेशकों के लिए पारिश्रमिक नीति सहित संबंधित पार्टी लेनदेन के अनुमोदन और प्रकटीकरण पर केंद्रित है। वार्षिक रिपोर्ट में संशोधन के लिए "संबंधित पार्टी प्रकटीकरण" की आवश्यकता है, किसी भी व्यक्ति या प्रमोटर या प्रमोटर समूह से संबंधित सूचीबद्ध संस्था के लेन-देन का खुलासा, जो सूचीबद्ध इकाई में 10% या अधिक की हिस्सेदारी है। यह खुलासा वार्षिक परिणाम के लिए प्रासंगिक लेखा मानकों में निर्धारित प्रारूप में भी होना चाहिए।

"संबंधित पार्टी" की परिभाषा को सूचीबद्ध इकाई के प्रवर्तक या प्रमोटर समूह से संबंधित किसी भी व्यक्ति या संस्था को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया है और सूचीबद्ध इकाई में 20% या अधिक शेयर होल्डिंग है. [54]

3. विशेष रूप से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संबंध में, सभी मीडिया कंपनियों को निर्देशक के विवरण, इक्विटी कैपिटल की हिस्सेदारी, शेयरहोल्डिंग पैटर्न, विदेशी निवेश, फंड के स्रोत, टेलीविजन चैनलों के अपलिंकिंग के लिए नीति दिशानिर्देशों के आधार पर धन की आवश्यकता होती है, 2011 भारत ने जारी किया MIB दिशानिर्देश, आवेदकों के लिए एक प्रारूप प्रदान करते हैं-अपलिंक चैनलों के लिए अनुमति लेने के लिए।

4.अपलिंकिंग दिशानिर्देशों में सभी कंपनियों की भी आवश्यकता होती है जो अपने चैनलों को पूरा खुलासा करने के लिए, आवेदन के समय, शेयरधारकों के समझौतों, ऋण समझौतों और ऐसे अन्य समझौतों के बारे में बताती हैं जिन्हें अंतिम रूप दिया जाता है या उनमें प्रवेश का प्रस्ताव है। इनमें से किसी भी बाद के बदलावों को पूर्ववर्ती समझौतों पर असर डालने वाले किसी भी बदलाव के 15 दिनों के भीतर एमआईबी को बताना होगा। अपलिंक और[55] / या डाउनलिंक[56] करने वाली कंपनियों को भी सालाना अपने ऑडिटेड रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं और कंपनी में डायरेक्ट्री, की-एग्जिक्यूटिव्स या फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट में बदलाव होने पर MIB को इंटिमेशन देना पड़ता है, ऐसा बदलाव होने के 15 दिनों के भीतर होता है[57]।.

5. जहां तक प्रिंट मीडिया का संबंध है, इसके लिए फॉर्म IV से आरएनआई के तहत इसके स्वामित्व पैटर्न का खुलासा करना आवश्यक है, जिसमें मालिक, साझेदारों और शेयरहोल्डिंग पैटर्न का नाम कुल पूंजी का एक प्रतिशत से अधिक है। हालांकि, शेयरधारकों को अपने स्वयं के प्रतिशत का खुलासा करने के लिए नहीं कहा जाता है और क्या विभिन्न शेयरधारकों के बीच कोई संबंध है।[58]

6. ऐसा प्रतीत होता है कि सार्वजनिक कंपनियों के लिए रिपोर्टिंग आवश्यकताएं, जहां तक खुलासे का संबंध है, निजी सीमित कंपनियों के लिए रिपोर्टिंग आवश्यकताओं की तुलना में अधिक कठोर हैं।[59]

7. एफएम रेडियो से संबंधित नीतिगत दिशानिर्देशों में यह आवश्यक है कि एक आवेदक को अपने व्यावसायिक या प्रबंधकीय क्षमता के प्रमाण के साथ निदेशकों के (i) नामों का

[53] https://www.nseindia.com/content/equities/SEBI_Circ_09092015.pdf

[54] https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-sebi-listing-obligations-and-disclosure-requirements-amendment-regulations-2018/$File/EY-sebi-listing-obligations-and-disclosure-requirements-amendment-regulations-2018.pdf

[55] https://mib.gov.in/sites/default/files/FinalUplinkingGuidelines05.12.2011.pdf

[56] https://mib.gov.in/sites/default/files/Downlinking_Guidelines05.12.11.pdf

[57] https://mib.gov.in/sites/default/files/Uplink_and_downlink_form_1%20%281%29.pdf

[58] http://asu.thehoot.org/resources/media-ownership/media-ownership-in-india-an-overview-6048

[59] https://scroll.in/article/694139/five-reasons-why-media-monopolies-flourish-in-india

खुलासा करना होगा। (ii) अन्य कंपनियों / संगठनों में निदेशकों द्वारा ऐसी कंपनियों / संगठनों के विवरणों के साथ निदेशक या अन्य कार्यकारी पदों के लिए उनके निदेशक (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और मुख्य वित्त अधिकारी, और वित्त के प्रमुखों) के उनके दावे (iii) का समर्थन करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य। विपणन और रचनात्मक विभाग, यदि कोई हो, अपनी व्यावसायिक योग्यता और प्रबंधकीय क्षमता के प्रमाण के साथ। अंशधारकों के समझौतों, ऋण समझौतों और ऐसे अन्य समझौतों का प्रकटीकरण जो अंतिम रूप दिया गया है या प्रस्तावित किए जाने का प्रस्ताव है। उपरोक्त किसी भी परिवर्तन के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सूचित किया जाएगा, किसी भी बदलाव के 15 दिनों के भीतर, पूर्वगामी समझौतों पर असर पड़ेगा।

3.3 जानकारी जिसका खुलासा किया जाना आवश्यक है।

1. उपरोक्त 3.1 / 2 में उल्लिखित जानकारी के अलावा मीडिया कंपनियों द्वारा जिन सूचनाओं का खुलासा किया जाना आवश्यक है, वे हैं:

- निर्देशकों का विवरण
- इक्विटी पूंजी का हिस्सा
- शेयरहोल्डिंग पैटर्न
- विदेशी निवेश, धन का स्रोत
- शेयरधारकों के समझौते,
- ऋण समझौते
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 90 में कहा गया है कि कंपनियों को अपने संबंधित संस्थाओं में लाभकारी शेयर रखने वाले व्यक्तियों के आधिकारिक रिकॉर्ड को बनाए रखने और उनके महत्वपूर्ण लाभ मालिकों के आरओसी प्रस्तुत विवरण के साथ रिटर्न दाखिल करने की भी आवश्यकता है।

मालिकों या उनके परिवार के सदस्यों की राजनीतिक संबद्धता का खुलासा करने के लिए कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। हालांकि, एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, 2011 की पॉलिसी दिशानिर्देशों में, एक राजनीतिक पार्टी को एक चैनल संचालित करने की अनुमति के लिए आवेदन करने से अयोग्य ठहराया जाता है।

यदि परिवार का सदस्य उसी कंपनी में निदेशक है, तो कंपनी अधिनियम, 2013 और अन्य विधानों के अनुसार, परिवार के सदस्य के नाम का खुलासा वार्षिक रिपोर्ट में किया जाएगा, हालांकि परिवार के सदस्य के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यक्ति जो कंपनी में किसी विशेष पद पर है।[60]

राजनीतिक संबद्धता आदि के संबंध में सूचना के गैर-प्रकटीकरण के साथ कठिनाई यह है कि राजनीतिक दलों और राजनीतिक संबद्धता वाले व्यक्तियों / मीडिया के बढ़ते वर्गों के नियंत्रण के रूप में, मीडिया को एक राजनीतिक सहयोगी के रूप में भी देखा जाता है और साथ ही मालिकों और संपादकों की निष्ठा के आधार पर मतदाता को प्रभावित करने की कोशिश करता है ।

हालाँकि किसी भी मीडिया कंपनी में राजनैतिक दल या उसके परिवार के सदस्यों के लिए किसी भी संबद्धता का खुलासा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हालांकि चुनाव प्रसारण के संबंध में एनबीएसए के स्व-नियामक दिशानिर्देशों में, यह दिशानिर्देश में कहा गया है कि "समाचार चैनल किसी भी राजनीतिक संबद्धता का खुलासा करेंगे। या तो किसी पार्टी या उम्मीदवार की ओर ... "जिससे जनता यह अनुमान लगा सकती है कि क्या एक विशेष समाचार चैनल, यदि वह इसे किसी पार्टी से राजनीतिक संबद्धता का खुलासा करता है, या तो पार्टी द्वारा वित्त पोषित है या अनिवार्य रूप से ऐसे राजनीतिक दल के स्वामित्व में है।[61]

2. TRAI ने मीडिया ओनरशिप पर 2014 की अपनी सिफारिशों में कहा था कि कुछ अनिवार्य रिपोर्टिंग के खुलासे के लिए मीडिया कंपनियों द्वारा MIB और TRAI को वार्षिक आधार पर किए जाने की आवश्यकता है:

(i) इकाई का साझाकरण पैटर्न;

(ii) इकाई का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पैटर्न;

(iii) मीडिया क्षेत्र में लगी अन्य संस्थाओं में इकाई के हित, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष;

(iv) संस्था के सदस्य, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, मीडिया इकाई में 5% से अधिक की हिस्सेदारी वाले, अन्य मीडिया संस्थाओं / कंपनियों में;

(v) शेयरधारक समझौते, ऋण समझौते और कोई अन्य अनुबंध / समझौता;

(vi) इकाई के प्रमुख अधिकारियों और निदेशक मंडल का विवरण;

(vii) और इकाई द्वारा किए गए ऋणों का विवरण;

(viii) इकाई / कंपनी की सदस्यता और विज्ञापन राजस्व;

(ix) सभी चैनलों के लिए जो MIB- पंजीकृत भाषा (नों) के संचालन के साथ समाचार चैनलों के रूप में पंजीकृत हैं, ऑपरेशन की वास्तविक भाषा (ओं), समाचार कार्यक्रमों के लिए समय स्लॉट;

(x) विज्ञापन दरें;

[60] http://asu.thehoot.org/resources/media-ownership/media-ownership-in-india-an-overview-6048

[61] http://www.nbanewdelhi.com/assets/uploads/pdf/12_Guidelines_for_Election_Broadcasts_3_3_14_E.pdf

(xi) इकाई के प्रत्येक मीडिया आउटलेट के लिए शीर्ष दस विज्ञापनदाताओं;

(xii) शेयर या किसी अन्य रूप में विज्ञापन स्थान की बिक्री के लिए प्राप्त आय;

(xiii) समाचार या संपादकीय स्थान की बिक्री के लिए नकद या किसी अन्य रूप में प्राप्त आय;

(बी) सार्वजनिक डोमेन में अनिवार्य रूप से रखे जाने के खुलासे निम्नानुसार हैं:

(i) किसी भी अन्य संस्था के साथ मीडिया इकाई के किसी भी रूप में एसोसिएशन, वित्तीय या अन्यथा, प्रकाशित / प्रसारित होने वाली वस्तुओं की सामग्री को प्रभावित करने के साथ पाठक / दर्शक को आइटम के प्रकाशन / प्रसारण के समय का खुलासा किया जाना चाहिए ।

(ii) सभी मीडिया संस्थाओं को अनिवार्य रूप से उन सभी संस्थाओं की सूची का खुलासा करना चाहिए जो इसे नियंत्रित करती हैं और जो इसे नियंत्रित करती हैं, उनके सभी मीडिया आउटलेट्स पर। इन खुलासों को टेलीविजन चैनलों के लिए स्क्रीन के निचले भाग में सूचनाओं की एक चलती रेखा के रूप में प्रति घंटे के अंतराल पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए, और अखबार के एक प्रमुख स्थान में, फ्रंट पेज के शीर्षक के ठीक नीचे[62] । ये सिफारिशें लंबित हैं।

3.4 सूचना की पहुंच

धारा 94 कंपनी अधिनियम 2013 के तहत, आरओसी उन कंपनियों से संबंधित एक रजिस्ट्री रखता है जो उनके साथ पंजीकृत हैं और आरओसी आम जनता को इस जानकारी को निर्धारित शुल्क के भुगतान पर एक्सेस करने की अनुमति देता है।[63]

इसके अलावा, सभी कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट को जनता द्वारा MCA[64] की साइट पर भी एक्सेस किया जा सकता है, जैसे दूरसंचार क्षेत्र के लिए वार्षिक रिपोर्ट DoT की वेबसाइट पर उपलब्ध है।[65]

RTI अधिनियम सभी "सार्वजनिक प्राधिकरणों" पर लागू होता है और एक व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से संबंधित जानकारी के लिए एक आवेदन कर सकता है। लोक प्राधिकरण को "किसी भी प्राधिकरण या निकाय या स्व-सरकार की संस्था के रूप में या संविधान के तहत या (क) के रूप में परिभाषित किया गया है; (ख) संसद द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा; (ग) राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा; (डी) उपयुक्त सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा, और इसमें कोई भी (i) निकाय शामिल, नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित; (ii) गैर-सरकारी संगठन उपयुक्त सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए धन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषित करते हैं।[66] यह अधिनियम सार्वजनिक प्रसारक, प्रसार भारती पर लागू होगा।

3.5 निगरानी और विनियमन

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 के तहत, वार्षिक रिटर्न दाखिल न करने पर दंड और वित्तीय सजा मिलती है। प्रतिबंधों से निपटने वाले अन्य खंड धारा 448 और 447 हैं जो गलत बयान दर्ज करने और धोखाधड़ी के लिए सजा को निर्धारित करते हैं।

- धारा 121 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित तरीके से वार्षिक आम बैठक में सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा रिपोर्ट दर्ज करने में विफलता के लिए वित्तीय दंड का प्रावधान करता है
- धारा 128 वित्तीय और दंडात्मक परिणामों के लिए प्रदान करता है यदि खातों की पुस्तकें, आदि कंपनी द्वारा बनाए नहीं रखी जाती हैं।

- धारा 129 - वित्तीय विवरणों के उचित प्रकटीकरण से संबंधित प्रावधानों का पालन करने में विफलता वित्तीय और दंडात्मक सजा को आकर्षित करती है।

- धारा 137, अधिनियम द्वारा प्रदत्त वित्तीय विवरणों की प्रति दायर करने में विफलता के मामलों में वित्तीय और दंडात्मक सजा का प्रावधान करता है।
- धारा 184 में निदेशक को किसी भी कंपनी या निकाय में अपनी रुचि का खुलासा करने की आवश्यकता होती है और प्रावधान का उल्लंघन अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए दंड और वित्तीय परिणामों को आकर्षित करता है।

- धारा 188 कंपनी के बोर्ड की सहमति प्राप्त करने के संबंध में अनुभाग की आवश्यकताओं का पालन करने में विफलता के मामलों में वित्तीय और दंड की सजा का प्रावधान करता है, संबंधित पार्टी लेनदेन के मामलों में एक संकल्प को रद्द करता है।

- सेबी के परिपत्रों और अधिसूचनाओं का उल्लंघन वित्तीय परिणाम आमंत्रित करता है।.

प्रिंट मीडिया के लिए, स्वामित्व पर जानकारी प्रदान करने में विफलता प्रेस और पंजीकरण अधिनियम, 1867 के तहत दंडात्मक दंड को आकर्षित करती है।

[62] https://main.trai.gov.in/sites/default/files/Recommendations_on_Media_Ownership.pdf
[63] http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/GuidelinesMCA_final_12022018.pdf
[64] http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/AnnualReport2017_18_19022018.pdf
[65] http://dot.gov.in/reports-statistic/2471
[66] https://rti.gov.in/rti-act.pdf

यदि कोई उसी की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो MIB प्रसारणकर्ताओं / रेडियो चैनलों की अनुमतियों को नवीनीकृत करने से इनकार कर सकता है या मना कर सकता है।

3.6 पारदर्शिता

सभी मीडिया कंपनियां अपनी वार्षिक रिपोर्ट दर्ज करती हैं और कानून द्वारा आवश्यक जानकारी का खुलासा करती हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या कानून को पूर्ण और प्रासंगिक डेटा का खुलासा करने की आवश्यकता है। प्रश्न का उत्तर इस तथ्य से पता चलता है कि TRAI ने 2014 में मीडिया स्वामित्व पर अपनी सिफारिशों में सुझाव दिया था कि आगे "प्रासंगिक खुलासे" क्षेत्र में वास्तविक पारदर्शिता को सक्षम और बढ़ाएंगे।[67] उपरोक्त के मद्देनजर, यह ध्यान दिया जाता है कि डेटा / सांख्यिकी या प्रारूप में शायद ही कोई एकरूपता है जिसमें विभिन्न प्रकार की कंपनियों / संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक डोमेन में डेटा प्रदान किया जाता है। विभिन्न विधानों के तहत आवश्यकताएं भी अलग-अलग होती हैं। आंकड़ों की खलबली से भ्रम पैदा होता है और महत्वपूर्ण आँकड़े डूब जाते हैं। इस तरह के डेटा का विश्लेषण करना आसान नहीं है, अकेले शेयरहोल्डिंग या स्वामित्व के पैटर्न की खोज करने के लिए विलय, समामेलन और अधिग्रहण से संबंधित जटिल लेनदेन को अलग कर दें।

उपरोक्त का एक प्रमुख उदाहरण रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट के माध्यम से नेटवर्क 18 कंपनियों के अधिग्रहण का बेहद जटिल लेनदेन है और फिर ईनाडू टीवी के चैनलों में दांव हासिल करने के लिए नेटवर्क 18 का करोड़ों का निवेश है।

अंत में केवल यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पारदर्शिता केवल तभी मौजूद है जब डेटा स्टैटिक्स में खो नहीं जाता है और जटिल कानून में निहित होता है।

स्थिति को स्क्रॉल में एक लेख के शीर्षक में अच्छी तरह से अभिव्यक्त किया गया है जो बताता है कि "मीडिया स्वामित्व के लिए प्रकटीकरण मानदंडों का कोई व्यापक ढांचा नहीं है"। चूंकि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत डेटा का खुलासा विभिन्न मापदंडों और एकत्रीकरण के स्तरों पर आधारित है, जिससे मीडिया के एकाधिकार और एकाग्रता की सीमा और विधि के बारे में तुलना और अध्ययन के लिए डेटा अनुपयोगी हो जाता है।[68]

4. अन्य राज्य मीडिया संगठनों को प्रभावित करते हैं।

4.1 राज्य कर और प्रभाव

1. जबकि मीडिया कंपनियों पर लगाए गए कर अन्य कंपनियों से अलग नहीं हैं, लेकिन प्रमुख विशेषता यह है कि प्रसारण उद्योग / मीडिया कंपनियों में कई हितधारक हैं- ब्रॉडकास्टर्स, डीपीओ (एमएसओ। डीटीएच, एचआईटीएस, आईपीटीवी) और एलसीओ और इसलिए व्यक्तिगत लेनदेन पर हितधारकों के बीच व्यक्तिगत रूप से कर लगाया जाता है।

2. प्री-जीएसटी शासन के तहत, 15% की दर से सेवा कर और अन्य करों जैसे प्रसारण सेवाओं पर मनोरंजन कर (डीटीएच / केबल टीवी सेवाएं) पर दोहरी लगान थी और इसलिए विभिन्न प्रमुखों के तहत प्रभारित दरें पूर्ववत थीं उच्च। राज्य स्थानीय कर लगाकर मनोरंजन उद्योग से उच्च आय पैदा कर रहे थे और इसलिए प्रसारण उद्योग केंद्रीय और राज्य करों का भुगतान कर रहा था विशेष रूप से मनोरंजन कई लेनदेन और सेवाओं का एक हिस्सा है जो व्यक्तिगत रूप से कर थे।

3. जीएसटी के लागू होने से 18% पर एकल लगान हुआ है जिससे कर का बोझ कम हुआ है और मनोरंजन / मीडिया उद्योग के लिए कर व्यवस्था सरल हो गई है।

जीएसटी से बाहर रोल के साथ यह भी संभावना है कि केबल व्यवसाय में अनुपालन में सुधार होगा जिससे प्रति क्षेत्र औसत राजस्व में सुधार होगा।

4. हालांकि प्रसारण उद्योग की कुछ चिंताएं बनी हुई हैं:

(i) भारत में प्रसारण क्षेत्र में विदेशी कंपनियों का कर उपचार देश में विदेशी निवेश को रोकने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक बन गया है। इसके कई उदाहरण हैं।

(ii) दूसरी बात यह है कि मीडिया क्षेत्र को कर के संबंध में जो अन्य नुकसान होता है, वह यह है कि औद्योगिक उपक्रम लाभ के लिए पात्र हैं और समामेलन के मामले में नुकसान की भरपाई के लिए, दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाले उपक्रम शामिल हैं, लेकिन मीडिया और मनोरंजन में उपक्रम क्षेत्र इसके आगे ले जाने के लिए पात्र नहीं हैं। क्षितिज पर दूरसंचार और मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के अभिसरण के साथ और क्षेत्र में समेकन की प्रवृत्ति देखी जा रही है, इस कर लाभ को मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में विस्तारित करने से मीडिया खिलाड़ियों के बीच समेकन को बढ़ावा मिलेगा और उनकी वृद्धि को बनाए रखना होगा ।[69]

(iii) तीसरे, जबकि सरकार ने सॉफ्टवेयर उत्पादन घरानों और विज्ञापन आयोगों को प्रसार के संबंध में टीडीएस पहलुओं को स्पष्ट करने के लिए परिपत्र जारी किया है / प्रसारकों द्वारा विज्ञापन एजेंसियों को दी गई छूट, लेकिन इस उद्योग द्वारा किए गए कुछ अन्य भुगतानों पर अभी भी बहुत विवाद है ।

(iv) चौथा, केबल ऑपरेटरों / मल्टी-सिस्टम ऑपरेटरों द्वारा प्रसारकों द्वारा कैरिज शुल्क का भुगतान कर विभाग द्वारा तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क के रूप में लिया जा रहा है, जो टीडीएस के लिए 10 प्रतिशत पर उत्तरदायी है और इसलिए इसके परिणामस्वरूप मुकदमेबाजी हुई है। इस तरह के

[67] Ibid p.26
[68] Ibid footnote 57
[69] https://www.moneycontrol.com/news/business/media-entertainment-industry-key-tax-issues-and-expectations-from-budget-2018-2489881.html

भुगतान 2 प्रतिशत की दर से टीडीएस के अधीन होने के प्रभाव का स्पष्टीकरण, प्रसारण से संबंधित 'काम' की ओर, इस मुद्दे पर मुकदमेबाजी को कम करने में मदद करेगा।

(v) इसके अलावा, डीटीएच उद्योग के लिए सेट टॉप बॉक्स / रिचार्ज कूपन वाउचर की बिक्री पर वितरकों को दी गई छूट पर टीडीएस की प्रयोज्यता लंबे समय से खींचा गया विवाद का एक अन्य क्षेत्र रहा है। सरकार को स्पष्टीकरण जारी करके इस विवाद को शांत करना चाहिए कि ऐसी छूट कमीशन की प्रकृति में नहीं है, और इसलिए यह टीडीएस के अधीन नहीं है।

(vi) 2012 में पेश की गई 'रॉयल्टी' की परिभाषा में पूर्वव्यापी संशोधन, हालांकि विधायी मंशा को स्पष्ट करने के उद्देश्य से किया गया था, ने प्रभावी रूप से आयकर अधिनियम, 1961 के तहत रॉयल्टी के दायरे का विस्तार किया है। कर प्राधिकरण, ट्रांसपोंडर किराया शुल्क के लिए प्रसारकों द्वारा भुगतान का इलाज एक 'प्रक्रिया' के उपयोग के लिए भुगतान करने के लिए कर रहे हैं (जो कि उपग्रह, केबल, आदि द्वारा ट्रांसमिशन को शामिल करने के लिए परिभाषित है) या उपकरण के उपयोग के लिए और इसलिए, 'रॉयल्टी' ', जो 10 प्रतिशत पर टीडीएस के लिए उत्तरदायी है। यहां तक कि जहां एक विदेशी उपग्रह कंपनी एक कर संधि द्वारा शासित होती है, वहीं कर प्राधिकरण संधि में आयकर अधिनियम के तहत परिभाषा का आयात कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप विदेशी उपग्रह कंपनियां भारतीय प्रसारकों को अपनी कर लागतों से गुजर रही हैं। भारतीय प्रसारकों पर मुकदमेबाजी और अनुचित बोझ को कम करने के लिए, सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि विदेशी प्रसारकों को भुगतान रॉयल्टी के लिए नहीं होता है और इस तरह भारत की स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के साथ जोड़ दिया जाता है।[70]

5. भारत में कराधान शासन जटिल है और आसानी से थाह लगाना मुश्किल है। जटिल कानून कई मुकदमों को जन्म देते हैं।

4.2 प्रवेश बाधा

मीडिया संगठनों के लिए प्रवेश बाधाएं निवेश और बुनियादी ढांचे की लागत के कारण अधिक हैं जो मीडिया व्यवसाय स्थापित करने के लिए आवश्यक हैं।

अपलिंकिंग चैनलों के लिए नीति दिशानिर्देशों के अनुसार: [71]

- टेलीपोर्ट- टेलीपोर्ट स्थापित करने की अनुमति के लिए तीन करोड़ रुपये के प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता होती है और इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त टेलीपोर्ट के लिए रु 1 करोर के अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता होती है।;

- समाचार और करंट अफेयर्स चैनल शुरू करने के लिए, कंपनी को रुपये के प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता होती है। पहले चैनल के लिए 20 करोड़ रुपये और उसके बाद किसी भी अतिरिक्त चैनल के लिए 5 करोड़ रुपये;

- एक गैर-समाचार चैनल शुरू करने के लिए, कंपनी को पहले चैनल के लिए 5 करोड़ रुपये के प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता होती है। और उसके बाद किसी भी अतिरिक्त चैनल के लिए 2.5 करोड़;

- आवश्यक अनुमतियों की सूची और एक टेलीविजन चैनलों को अपलिंक करने की प्रक्रिया लंबी, थकाऊ और बोझिल है। उपरोक्त प्रक्रिया में शामिल अधिकारी / विभाग हैं: एमआईबी; गृह मंत्रालय; DoS; dor; WPC; NOCC; दूरसंचार विभाग

- इस प्रक्रिया मे MIB के साथ 2 स्टेज हैं जिसमें एक है MHA, DoS और DoR के इनपुट पर विचार किया जाता है और फिर प्रसारण सेवाओं के लिए आशय पत्र या अनुमति पत्र जारी करने का निर्णय लिया जाता है।

- टेलीविजन या रेडियो प्रसारण के लिए नीलामी के माध्यम से या FCFS आधार पर स्पेक्ट्रम का आवंटन एक थकाऊ प्रक्रिया है, चाहे;

- वाणिज्यिक रेडियो स्टेशन या सीआरएस शुरू करना मौद्रिक रूप से बहुत महंगा है।

- आवृत्तियों का मूल्य निर्धारण नए उद्यमियों के लिए एक समस्या पैदा कर सकता है यदि कीमत अधिक है;

ये बाधाएं किसी भी नए प्रवेशकर्ता के सामने आने वाली नियमित कठिनाइयों से अलग हैं:

(i) एक नए प्रवेश के लिए इस क्षेत्र / उद्योग में प्रतिस्पर्धा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, विशेष रूप से क्षेत्रीय प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में निषिद्ध है;

(ii) प्रतियोगिता के मद्देनजर, पर्याप्त कुशल कर्मचारियों, विशेषज्ञों को प्राप्त करने और वितरण प्लेटफार्मों तक पहुंच एक समस्या है;

(iii) विज्ञापन के लिए सामग्री के कैरिज की लागत, कवरेज की लागत और राजस्व के लिए प्रतिस्पर्धा एक गंभीर बाधा साबित हो सकती है;

(iv) डिजिटल मीडिया के आगमन के साथ, न केवल प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, बल्कि पारंपरिक मीडिया को अधिक उपभोक्ताओं को

[70] Ibid footnote 67

[71] https://www.broadcastseva.gov.in/Landing%20Page%20Documents/Satellite%20TV%20Channels-2017-5-19/FinalUplinkingGuidelines05.12.2011.pdf

आकर्षित करने और प्रासंगिक सामग्री और सेवाओं को वितरित करने के लिए लगातार नए विचारों के साथ आना होगा जो लाभदायक भी हैं।[72]

नियामक, TRAI ने "ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग बिजनस" पर 26 वीं तारीख, 2018 की सिफारिशों में स्वीकार किया था [73] कि प्रसारण क्षेत्र में लाइसेंस / अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया अप्रचलित, अक्षम और आवश्यक री-इंजीनियरिंग थी। इसने कहा कि प्रसारण क्षेत्र में प्रवेश बाधाओं को दूर करने के लिए, अच्छी तरह से परिभाषित और पारदर्शी प्रक्रियाएं करना, क्षेत्र में नवाचार, प्रौद्योगिकी को अपनाने और निवेशक अनुकूल नीतियों को पेश करना महत्वपूर्ण था। वर्तमान में MIB के भीतर कई विभागों से आवश्यक कई स्तरों की मौजूदगी है।

4.3 मीडिया एकाग्रता और स्पेक्ट्रम आवंटन

मीडिया एकाग्रता ने स्पेक्ट्रम आवंटन में एक हद तक भूमिका निभाई है कि आवृत्तियों के उच्च मूल्य निर्धारण से यह सुनिश्चित होता है कि राष्ट्रीय / प्रमुख प्रतिस्पर्धी / कंपनियां स्पेक्ट्रम की नीलामी में बोलियां जीतती हैं और इस तरह उद्योग में अपने पैर जमाने में कामयाब होती हैं। उसी का एक उदाहरण नीचे दिया गया है:

(ए) रेडियो आवृत्तियों की नीलामी के चरण III में, मूल्य निर्धारण अत्यधिक था और इसने नए प्रवेशकों को आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने से रोक दिया।

(बी) 2015 में, एमआईबी को चरण III ई-नीलामी के लिए कुल 28 आवेदन प्राप्त हुए; जिसमें से लगभग 13 नए प्रवेशकर्ता थे। हालांकि, बोली के अंत तक (या नीलामी) केवल पांच नए प्रवेशकर्ता थे जिन्होंने विभिन्न आवृत्तियों का अधिग्रहण किया, जिनकी कीमत 0.29 रुपये से 7.40 करोड़ रुपये के बीच थी।

(सी) सार्थक फिल्म्स प्रा। लिमिटेड, ओडिशा टेलिविज़न लिमिटेड, अभिजीत रियल्टर्स एंड इन्फ्रावेर्स प्रा। लिमिटेड, रेंडरलाइव फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट प्रा। लिमिटेड, और एबिरबिल्डकन प्राइवेट। लिमिटेड, रेडियो उद्योग में नए प्रवेशकों थे।

(डी) शाही शिपिंग लिमिटेड, प्रतिदिन एफएम प्राइवेट लिमिटेड और एएम टेलीविज़न प्राइवेट लिमिटेड जैसे अन्य नए प्रवेशकर्ता रेडियो उद्योग में प्रवेश करने में विफल रहे और रेडियो फ्रीक्वेंसी अवशेष 'प्राप्त करने के लिए इंतजार करना पड़ा।

(ई) आवृत्तियों के मूल्य निर्धारण और फुलाए गए लागत के कारण बहुत कम नए प्रवेशकर्ता थे जो नीलामी की आवृत्तियों का अधिग्रहण करने में कामयाब रहे

(ए) हालांकि बड़ी कंपनियों, या दूसरे शब्दों में, मौजूदा राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी लाखों में बोली लगाने के लिए चले गए, ज्यादातर नए प्रवेशकों ने फुलाया लागतों के प्रभाव को महसूस किया। प्रेटिडिन एफएम प्राइवेट लिमिटेड, जो पूर्वोत्तर स्थित प्रेटिडिन समूह का हिस्सा है, को हाल ही में रेडियो व्यवसाय चलाने के लिए पंजीकृत किया गया था। प्रितिन एफएम प्राइवेट लिमिटेड के प्रवर्तकों में से एक, ऋषि बरुआ लिमिटेड ने कहा, "हम एक बिंदु पर रुक गए क्योंकि हमारे शोध ने साबित कर दिया कि बाजार, हम देख रहे थे कि लाभदायक नहीं हो सकता क्योंकि कीमतें आसमान छू रही थीं।" [74]

मीडिया एकाग्रता स्पेक्ट्रम आवंटन में विशेष रूप से क्षेत्रीय क्षेत्रों या विशेष रूप से क्षेत्रीय क्षेत्रों में बड़ी कंपनियों के पक्ष में भूमिका निभाता है जहां कुछ चैनलों का पहले से ही बाजार प्रभुत्व है।

4.4 स्पेक्ट्रम आवंटन में पारदर्शिता

1. प्रसारकों के बीच आवृत्तियों के आवंटन के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया बहुत पारदर्शी, खुली या सहभागितापूर्ण नहीं रही है, जो 2 जी स्पेक्ट्रम मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में परिलक्षित होती है जिसका शीर्षक ए. राजा वर्सस सुब्रमण्यम स्वामी [75]' उपर्युक्त निर्णय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार पर लाइसेंस रद्द कर दिया था कि एफसीएफएस के आवंटन स्पेक्ट्रम के लिए अपनाई गई प्रक्रिया मनमानी और अनियमित थी। सरकार के फैसलों की जांच करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैसले "मनमाना," "असंवैधानिक," और "अवैध" थे। विश्लेषकों ने शिकायत की कि संभावित राजस्व में अरबों का नुकसान हुआ क्योंकि 2 जी लाइसेंस बाजार मूल्य से नीचे बेचे गए थे। शीर्ष अदालत ने यह भी देखा कि नीलामी ने दुर्लभ संसाधनों के आवंटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और नीलामी को आर्थिक दक्षता के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करने और हाल ही में राजस्व का अनुकूलन करने के सर्वोत्तम रूपों में से एक पाया गया है। प्रतियोगिता इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का महत्वपूर्ण उपकरण है जो इसे देखा गया है। आमतौर पर प्रचलित नीलामियों के दो डिजाइन अनिवार्य रूप से होते हैं - ए) आरोही नीलामी, जिसमें एक बोलीदाता के रहने तक मूल्य सफलतापूर्वक उठाया जाता है और बी) सील बोली नीलामी, जिसमें बोलीदाता स्वतंत्र रूप से दूसरों की बोली देखे बिना एक ही बोली को प्रस्तुत करता है और वस्तु को उच्चतम बोली में बेचा जाता है। आरोही नीलामियों के रूप में अच्छी तरह से निरोधात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करने की संभावना है।[76]

2. उसके बाद, NFAP-2018 को तैयार किया गया था जो DoT [77] की वेबसाइट पर उपलब्ध है और यह एक व्यापक विनियामक ढांचा प्रदान करता है, जिससे पता चलता है कि सेलुलर मोबाइल सेवा, वाई-फाई, साउंड और टेलीविज़न प्रसारण, रेडियो

[72] https://www.equitymaster.com/research-it/sector-info/media/Media-Sector-Analysis-Report.asp
[73] https://main.trai.gov.in/sites/default/files/Recommendation_EODB_26022018.pdf
[74] http://www.radioandmusic.com/biz/radio/private-fm-stations/151004-how-did-new-entrants-radio-industry-fare
[75] A. Raja Versus Subramanian Swamy 2012 (9) SCC 257
[76] https://main.trai.gov.in/sites/default/files/CUTS_plimanry.pdf
[77] http://wpc.dot.gov.in/WriteReadData/userfiles/NFAP%202018.pdf

नेविगेशन के लिए कौन से फ्रीक्वेंसी बैंड उपलब्ध हैं विमान और जहाज, रक्षा और सुरक्षा संचार, आपदा राहत और आपातकालीन संचार, उपग्रह संचार और उपग्रह-प्रसारण, और शौकिया सेवाएं। एनएफएपी -18, हालांकि भारत में स्पेक्ट्रम के उपयोग को नियंत्रित करता है, लेकिन स्वयं स्पेक्ट्रम का उपयोग करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है।

3. स्पेक्ट्रम का आवंटन करने वाले प्राधिकरण DoT और WPC हैं। हालांकि, DoT एक केंद्र सरकार का मंत्रालय है और इसे स्वतंत्र विंग माना जाता है, लेकिन वाणिज्यिक निहित स्वार्थ वाली संस्थाओं द्वारा राजनीतिक हस्तक्षेप या हस्तक्षेप की संभावना हमेशा सुस्त रहती है। स्पेक्ट्रम के किसी भी हिस्से को भारत में उपयोग करने के लिए, डब्ल्यूपीसी विंग, संचार मंत्रालय से लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, जब तक कि ऐसी आवश्यकता को डब्ल्यूपीसी विंग द्वारा छूट नहीं दी जाती है। नीलामी में भाग लेने के लिए, प्रतिभागियों को अलग-अलग फ्रीक्वेंसी बैंड के संबंध में DoT द्वारा जारी किए गए नोटिस इनवाइटिंग एप्लिकेशन के नियमों और शर्तों का पालन करना होता है।

4. स्पेक्ट्रम नीलामी के साथ भारत के पिछले अनुभव ने अक्सर यह बताया है कि सरकार का ध्यान अल्पकालिक राजस्व अधिकतमकरण पर भारी रहा है। यह क्षेत्र के लंबे समय तक स्वस्थ विकास की लागत पर किया गया है और संभवतया एक संपन्न दूरसंचार क्षेत्र से उच्च कर आय के माध्यम से सरकार के लिए लंबे समय तक राजस्व का अधिकतमकरण है। स्पेक्ट्रम के लिए अत्यधिक आरक्षित मूल्य फर्मों के लिए निर्धारित लागत को बढ़ाता है और साथ में क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के उच्च स्तर के साथ लंबे समय में आवश्यक रूप से उपभोक्ता अधिशेष को प्रभावित करता है। इसलिए इस क्षेत्र में कम नवाचार और अंततः सेवा की गुणवत्ता खराब हो गई।

5. उपरोक्त टिप्पणियों को सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी, ब्रुकिंग्स द्वारा किए गए एक अध्ययन में किया गया था, जिसमें विश्लेषकों द्वारा बताया गया था कि "भारत में स्पेक्ट्रम की लागत दुनिया में सबसे अधिक है।"[78] स्पेक्ट्रम के संबंध में एक और समस्या देखी गई। अनम्य और खंडित उपयोग। तब से, भारत में अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं के बीच आम सहमति है कि नीलामी स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए एक बेहतर तंत्र है। स्पेक्ट्रम नीलामियों के दोहरे उद्देश्यों को देखते हुए - सबसे अधिक उपयोग और सरकारी राजस्व को अधिकतम करने के लिए स्पेक्ट्रम का कुशल आवंटन - यह महत्वपूर्ण है कि नीलामियों को उचित रूप से डिज़ाइन किया गया है। नीलामी की मौलिक प्रक्रिया मूल्य खोज है। हालांकि, सरकारी नीलामी ने कीमतों को अनुचित स्तर तक बढ़ा दिया और दूरसंचार कंपनियों को उच्च ऋण स्तर पर ले जाने के लिए मजबूर किया।

6. वर्तमान में यह ध्यान दिया जा सकता है कि DoT E और V बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं करने पर विचार कर रहा है और इन एयरवेव्स को आवंटित करने की योजना बना रहा है ताकि ऑपरेटर इसका उपयोग अपने नेटवर्क पर क्षमता उन्नयन के लिए कर सकें, डेटा खपत में वृद्धि को देखते हुए।[79] इस रणनीति का तात्पर्य है कि स्पेक्ट्रम को केवल FCFS आधार के माध्यम से जारी किया जाना है क्योंकि हस्तक्षेप के मामले में पहले ऑपरेटर द्वारा स्थापित नेटवर्क को संरक्षित किया जाना है[80] । 5G ट्रायल नेटवर्क के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन भी विचाराधीन है।

4.5 राज्य विज्ञापन का वितरण

1. भारत में सरकारी विज्ञापन का प्रबंधन DAVP द्वारा किया जाता है जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए मल्टी-मीडिया विज्ञापन और प्रचार करने के लिए नोडल एजेंसी है। नीति और मिशन DAVP की वेबसाइट[81] पर कहा गया है। हालाँकि, जिस आधार पर DAVP ने समाचार पत्रों को या हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया / रेडियो को राज्य विज्ञापन वितरित किए हैं, वह पारदर्शी नहीं है और न ही इसकी नीति या व्यवहार उचित है।

2. DAVP विशेष रूप से प्रिंट मीडिया में सबसे बड़ा विज्ञापनदाता है। निजी सी एंड एस टीवी चैनलों के निजीकरण और सरकारी विज्ञापनों के लिए दरों के निर्धारण की नीति को पिछली बार 2017[82] में संशोधित किया गया था और 2016[83] में प्रिंट के लिए। रेडियो के लिए, एफएम रेडियो स्टेशनों के लिए निजीकरण और सरकारी विज्ञापन के लिए दरों के निर्धारण के लिए नीति दिशानिर्देश 2016[84] में संशोधित किए गए थे। .

(i) रेडियो और टेलीविज़न के लिए सरकार की विज्ञापन दरें चैनलों की पहुँच के अनुसार वितरित की जाती हैं और यह BARC और IRS द्वारा लाए गए आंकड़ों से पता चलता है जो चैनलों को देखने या सुनने वाले दर्शकों को निर्धारित करता है।

(ii) हालांकि, BARC डेटा के आधार पर विज्ञापन वितरित करने में कई समस्याएं हैं जैसे कि स्थापित किए गए सैंपल पैनल पर्याप्त नहीं हैं, पैनल के साथ अभी भी छेड़छाड़ की जा सकती है, आला चैनलों के डेटा गलत रहते हैं, समाचार चैनलों का डेटा भी सही नहीं है और ग्रामीण / शहरी डेटा गलत है

(iii) प्रिंट मीडिया के संबंध में, हाल ही में DAVP नीति को संशोधित किया गया था, जिसमें अखबारों को प्रोत्साहित करने के लिए समाचार पत्रों के लिए एक नई अंकन प्रणाली शुरू की गई थी, जिसमें बेहतर पेशेवर खड़े हों। इन अखबारों को अब

[78] https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2017/05/spectrum-policy-in-india8515.pdf

[79] https://www.livemint.com/Industry/TYhSyudzRVf69px5KeKuwN/DoT-seen-allocating-spectrum-in-E-V-bands-without-an-auctio.html

[80] https://thewire.in/business/modi-govt-to-allocate-valuable-spectrum-on-first-come-first-serve-basis

[81] http://www.davp.nic.in/

[82] http://davp.nic.in/writereaddata/announce/TV%20Amendment_31_8_2017.pdf

[83] http://www.davp.nic.in/Newspaper_Advertisement_Policy.html

[84] http://davp.nic.in/writereaddata/announce/Adv6131282016.pdf

ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन या RNI द्वारा अपने सर्कुलेशन को सत्यापित करवाना होगा। नीति ने समाचार पत्र / पत्रिकाओं को लघु, मध्यम और बड़े तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। नीति यह भी निर्दिष्ट करती है कि लगभग 30% विज्ञापन अंग्रेजी भाषा में, 35% हिंदी में और 35% क्षेत्रीय और अन्य भाषाओं जैसे बोडो, डोगरी, गढ़वाली, कश्मीरी, खासी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मिज़ो, नेपाली में होने चाहिए। राजस्थानी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, उर्दू और जनजातीय भाषाएँ।

(iv) DAVP द्वारा जारी किए गए विज्ञापनों के लिए भुगतान की संरचना का पता एक दर संरचना समिति द्वारा लगाया जाता है।

(v) हालांकि, अतीत में, प्रिंट मीडिया के संबंध में DAVP द्वारा विज्ञापन वितरित करने की प्रथा को अक्षम और पक्षपाती बताया गया था। द हिंदू में एक रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 28/05/2015:[85]

- विज्ञापन जारी करने के लिए समाचार पत्रों / पत्रिकाओं के चयन के संबंध में भ्रष्टाचार था;
- समाचार पत्रों की विस्फोटक वृद्धि से निपटने के लिए DAVP ने प्रौद्योगिकी का लाभ नहीं उठाया था;
- शायद ही किसी अख़बार ने आवश्यक वार्षिक विवरण प्रस्तुत किया हो;
- केवल 40% समाचार पत्रों को विज्ञापनदाताओं की विशेषाधिकार प्राप्त DAVP सूची में मिला;
- समाचार पत्रों के चयन की प्रणाली कठिन और पुरानी थी;
- कीमत का निर्धारण तर्कहीन था और इसलिए कई विज्ञापनदाताओं को विज्ञापन पाने से दूर रखा;
- प्रणाली नौकरशाही थी;
- DAVP में गुणवत्ता वाले छोटे कागजात की गुणवत्ता में कमी और उनकी सामग्री का आकलन करने के लिए, छोटे कागजात के लिए 15 प्रतिशत का मतलब उन भ्रष्ट लोगों तक पहुंचना था जो राजनीतिक रूप से अच्छी तरह से जुड़े हुए या भ्रष्ट सौदों के माध्यम से समाप्त हो गए थे;
- गहरी जेब वाले बड़े अखबारों ने विज्ञापनों को प्राप्त करने के लिए DAVP में हेरफेर करने में सक्षम थे;
- छोटे अखबारों और बड़े अखबारों को विज्ञापन दिए जाने की दर विचित्र थी और बड़े प्रसार के साथ अखबार के प्रति पक्षपाती थी। जबकि बड़े अखबारों की अपनी संपत्तियां ऐतिहासिक लागतों पर हासिल की गई थीं, लेकिन छोटे कागजात को अक्सर बुनियादी ढांचे पर बहुत अधिक लागत का खर्च उठाना पड़ा। बैंकों और अन्य स्रोतों से वित्त लागत ने बड़े कागजात के लिए उपलब्ध लोगों के एक अंश का गठन किया;
- छोटे अखबारों ने DAVP द्वारा दी गई दर को इतना अनुचित पाया कि वे DAVP से दूर रहे।
- छोटे और विशेष प्रकाशनों की मृत्यु दर अधिक थी
- चूंकि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के प्रवेश के साथ विज्ञापनों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी, इसलिए बड़े अंग्रेजी अखबार मुख्य रूप से और विज्ञापनों पर निर्भर हो गए। यह छोटे संसाधनों के लिए छोटे संसाधनों के लिए एक असमान प्रतियोगिता थी जो इन विज्ञापनों को पूरा करने के लिए प्रतिस्पर्धा करती थी;
- अधिकांश बड़े समाचार पत्र बड़े औद्योगिक घरानों से संबंधित हैं। उदारीकरण के बाद, मीडिया मुगलों और राजनेताओं के बीच सांठगांठ बढ़ गई। कई मीडिया हाउसों ने बिजली, कोयला और शराब जैसे अन्य व्यवसायों में विस्तार किया है। बड़े अखबारों द्वारा प्रकाशित कवर-जैकेट विज्ञापनों ने दरों में शानदार छूट की पेशकश की; कुछ लोगों ने छोटे व्यवसायों को बड़े पैमाने पर विज्ञापन देने के लिए इक्विटी सौदों की पेशकश की।
- बड़े अखबारों द्वारा प्रभावी पैरवी करने से उन्हें केंद्र और राज्यों में चुनावों या शासन की वर्षगांठ जैसे विशेष अवसरों पर विज्ञापनों की एक झलक पाने में मदद मिली।

(vi) सीसीआई के समक्ष एक मामले में विज्ञापन एजेंसियां गिल्ड बनाम DAVP और एमआईबी 'केस नंबर २१/२०१२ के मामले में, सीसीआई ने कहा कि याचिकाकर्ता का आरोप है कि DAVP एक प्रभावी स्थिति में थी और उसका प्रभुत्व खत्म हो गया था और इसलिए स्थापित नहीं किया गया था। सरकारी विज्ञापनों के लिए 'नोडल' एजेंसी के रूप में DAVP से अलग DAVP के मामले को खारिज कर दिया।

(vii) DAVP द्वारा जारी विज्ञापनों की दरों के संबंध में निजी टेलीविजन चैनलों द्वारा कई समस्याएं हैं। इसकी 2017 की नीति में, विज्ञापन के लिए DAVP की दर बहुत कम थी, जबकि पांच बार बैंड दिए गए थे, लेकिन कोई फैलाव प्रतिशत निर्दिष्ट नहीं किया गया था। अन्य समस्याग्रस्त बिंदु यह प्रतीत होते हैं कि BARC का डेटा समाचार शैली के लिए उपयोग किया जाता है, चाहे ग्रामीण या शहरी ने पूरी तस्वीर न दी हो और न ही पहुंच, DAVP द्वारा भुगतान स्पष्ट होने में लंबा समय लगा था और भुगतान की पेंडेंसी बहुत अधिक थी[86].

3. वास्तव में जनवरी 2019 तक, DAVP ने अपनी सरकारी विज्ञापन दरों में 11% की वृद्धि की है, जो एक निजी उपग्रह टेलीविजन चैनल है और इस तरह के विज्ञापन BARC द्वारा निर्धारित अपनी पहुंच और टीवी रेटिंग के आधार पर चैनलों के बीच वितरित किए जाते हैं, एकमात्र एजेंसी जो काम करती है निजी समाचार और सामान्य मनोरंजन चैनलों के लिए टेलीविजन

[85] http://www.industrialeconomist.com/page.php?page=80&cid=1053

[86] http://www.nbanewdelhi.com/assets/uploads/pdf/10TH_AR_2016-17.pdf

रेटिंग के साथ। समाचार और सामान्य मनोरंजन चैनलों की दरें अलग-अलग हैं।[87] प्रिंट मीडिया की दरों में भी 25% की वृद्धि की गई। यह देखा जाना चाहिए कि क्या DAVP की विज्ञापन दरों में वृद्धि और नीतियों में किए गए बदलावों के साथ मीडिया को राज्य के विज्ञापन का वितरण उचित और पारदर्शी हो गया है या नहीं।

4.6 राज्य विज्ञापन की निगरानी

सरकार के पास DAVP विज्ञापनों के अस्तित्व, आवधिकता और प्रसार की जांच करने के लिए मशीनरी है और इसलिए एक प्रकाशन के अस्तित्व, इसकी नियमितता, सामग्री और इसके प्रिंट की जांच करना मुश्किल काम नहीं होगा। प्रत्येक मुद्दे की प्रतियों को निर्दिष्ट केंद्रीय पुस्तकालयों और आरएनआई को भेजना भी अनिवार्य है। हालांकि, सवाल यह है कि क्या नियमित आधार पर जांच और निगरानी की जाती है? DAVP में नागरिक चार्टर ने एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है यदि कोई व्यक्ति DAVP की सेवाओं से संतुष्ट नहीं है। नोडल अधिकारी नागरिक चार्टर के कार्यान्वयन और निगरानी और सेवा वितरण के मानदंडों / मानकों के लिए जिम्मेदार है। वह निदेशालय स्तर पर नामित लोक शिकायत अधिकारी भी हैं। यदि कोई व्यक्ति लोक शिकायत अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रतिक्रिया से असंतुष्ट है, तो वह व्यक्ति MIB में शिकायत अधिकारी से शिकायत कर सकता है।

4.7 कानून का मीडिया व्यवसाय के साथ हस्तक्षेप

अनुच्छेद 19 (2) के तहत संविधान में उल्लिखित प्रतिबंध राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, अपराध के लिए उकसाना और भारत की संप्रभुता और अखंडता हैं। केवल मीडिया के मुक्त भाषण अधिकारों और सभी विधानों पर प्रतिबंधों का इस नींव पर परीक्षण किया जाना है।

1. हालांकि ऐसे कई विधानों को औपनिवेशिक युग के संशोधनों के साथ या तो फंसाया गया है या बरकरार रखा गया है, जो मीडिया / सेवा के मुक्त भाषण को प्रभावित करते हैं:

- सरकारी गोपनीयता अधिनियम। 1923 राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित।
- आईटी एक्ट, 2000 की धारा 66 ए जो कि श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के मामले[88] में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दी गई थी क्योंकि इसमें कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मेल या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजेगा झुंझलाहट या असुविधा पैदा करने या धोखा देने या ऐसे संदेश की उत्पत्ति के बारे में पता या प्राप्तकर्ता को भ्रमित करने के उद्देश्य से मेल संदेश को दंडित किया जाएगा। शीर्ष न्यायालय ने अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रता की स्वतंत्रता के उल्लंघन के आधार पर ऑनलाइन भाषण पर प्रतिबंध से संबंधित धारा को असंवैधानिक पाया। न्यायालय ने आगे कहा कि अनुच्छेद 19 (2) के तहत बोलने की स्वतंत्रता पर 'उचित प्रतिबंध' होने के कारण धारा को बचाया नहीं गया था।

हालाँकि, उपरोक्त निर्णय के बाद भी, ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहाँ व्यक्तियों को पुलिस द्वारा इस आधार पर गिरफ्तार किया गया था[89] कि ऑनलाइन उनके पद कथित तौर पर उक्त धारा के हिंसक थे।[90]

2. 14 फरवरी और 15 फरवरी, 2013 को DoT ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को पांच अलग-अलग आदेश जारी किए, जिससे 164 यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर या वेब एड्रेस तक पहुंच अवरुद्ध हो जाती है जहां विशिष्ट सामग्री की मेजबानी की जाती है। सभी पांचों को निर्विवाद रूप से निर्विवाद रूप से जारी किया गया और अदालतों से निकलने वाले पूर्व पक्षपातपूर्ण आदेशों के साथ अनारक्षित अनुपालन किया गया। कोई कारण नहीं दिया गया था, हालांकि जैसे-जैसे चीजें बदलीं, ये पता लगाना बहुत मुश्किल नहीं था।[91]

- आईपीसी की धारा 499 और 500 आपराधिक मानहानि और सजा से संबंधित है। हालाँकि, सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ और अन्य में भारत[92] के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त प्रावधानों की वैधता को बरकरार रखा गया है, फिर भी ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ लेख प्रकाशित नहीं होने पर मीडिया या पत्रकारों को परेशान करने के लिए इन प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया है व्यक्ति / संगठन के लिए ।
- इस तरह के प्रावधान के तहत मामला दर्ज करने का इरादा यह सुनिश्चित करना है कि प्रकाशन लेख को वापस ले लेता है या इसे प्रकाशित करने के लिए माफी मांगता है। एक बार आईपीसी के ऐसे प्रावधान लागू होने के बाद आपराधिक मामलों और चिंताजनक / दंडात्मक दंड के परिणामस्वरूप मामलों और चिंता का विषय होने के बाद से मीडिया और उसके पत्रकारों पर इसका "प्रभाव" पड़ सकता है।

[87] https://theprint.in/india/governance/modi-govt-hikes-ad-rates-for-private-channels-looks-to-boost-tv-presence-ahead-of-polls/183351/
[88] AIR 2015 SC 1523
[89] https://www.huffingtonpost.in/2018/10/15/the-supreme-court-struck-down-section-66a-of-the-it-act-in-2015-why-are-cops-still-using-it-to-make-arrests_a_23561703/
[90] https://www.business-standard.com/article/current-affairs/police-using-section-66a-of-it-act-to-make-arrests-despite-sc-s-ruling-118120300067_1.html
[91] https://www.epw.in/journal/2013/09/web-exclusives/quashing-dissent-where-national-security-and-commercial-media
[92] 2016 (7) SCC 221

- सिविल मानहानि के मुकदमे और मीडिया के खिलाफ प्रार्थना की जाने वाली हर्जाना भी मीडिया को वापस लेने या उसके प्रकाशन के लिए माफी मांगने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण हैं। यदि मांगे गए नुकसान बड़े हैं, तो यह एक विवादास्पद मीडिया कंपनी को एक लंबी और महंगी मुकदमेबाजी प्रक्रिया से गुजरने के बजाय मामले को निपटाने के लिए मजबूर कर सकता है।

(i) 55 मामले जयललिता सरकार ने मीडिया के खिलाफ दायर किए थे।[93]

(ii) स्पष्ट रूप से हिंदू अखबार के खिलाफ तमिलनाडु सरकार द्वारा १२५ मामले दर्ज किए गए थे।[94]

(iii) मीडिया के खिलाफ अनिल अंबानी समूह द्वारा 28 मानहानि के मुकदमे दायर किए गए ।[95]

2016 में मानहानि को कम करने का प्रयास विधेयक की प्रस्तावना - भाषण और प्रतिष्ठा संरक्षण विधेयक, 2016 के साथ किया गया है।[96]

- धारा 294 आईपीसी (सार्वजनिक रूप से अश्लील कृत्यों या शब्दों के लिए सजा);
- धारा 153 (ए) आईपीसी (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) आईपीसी;
- आईटी अधिनियम की धारा 67 जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने की बात करती है जो अश्लील है;
- आईटी अधिनियम की धारा 69 सरकार को किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी सूचना के अवरोधन या निगरानी या डिक्रिप्शन के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की अनुमति देती है और इस तरह के निर्देश भारत की संप्रभुता या अखंडता की रक्षा करने के लिए जैसे परिस्थितियों में जारी किए जा सकते हैं, वास्तव में। प्रसारकों को अपने चैनलों को अपलिंक करने के लिए जारी की गई अनुमति यह भी बताती है कि यदि प्रसारणकर्ता CTN अधिनियम, 1995 और CTN Rules1994 के प्रोग्राम कोड का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें उत्तरदायी ठहराया जाएगा। प्रोग्राम कोड में कुछ शब्द व्यक्तिपरक व्याख्या के लिए उत्तरदायी हैं।
- भारत में राजद्रोह का अपराध, आईपीसी की धारा 124-ए के तहत परिभाषित किया गया है, "जो कोई भी या तो शब्दों के द्वारा या लिखित या संकेतों द्वारा, या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा या अन्यथा घृणा या अवमानना या उत्तेजना में लाता है या करने का प्रयास करता है भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति उत्साह को दंडित किया जाएगा "। यह पुरातनपंथी कानून हो सकता है और मीडिया पत्रकारों के खिलाफ इसका दुरुपयोग हो सकता है।

ऐसा ही एक उदाहरण है श्री कमल शुक्ला; एक पत्रकार पर लेट जस्टिस लोया की रहस्यमय मौत के मामले में जांच पर फेस बुक पर उनके पदों के लिए उक्त प्रावधान के तहत आरोप लगाया गया था।[97] एक अन्य मामले में जेएनयू के छात्रों पर भारत विरोधी नारे लगाने के आरोप में देशद्रोह का आरोप लगाया गया था।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) भारत की नियामक फिल्म संस्था, नियमित रूप से निर्देशकों को आदेश देती है कि वे ऐसी किसी भी चीज को हटा दें, जिसमें यौन, नग्नता, हिंसा या राजनीतिक रूप से विध्वंसक माने जाने वाले विषय शामिल हैं।

3. एक व्यावहारिक स्तर पर, मीडिया कंपनियां विभिन्न कानूनों के तहत पीड़ित हैं या नहीं, जिनमें आयकर अधिनियम, सेबी अधिनियम और बैंकिंग विनियम आदि के प्रावधानों का उल्लंघन शामिल है, यह भी इस बात पर निर्भर कर सकता है कि उक्त मालिक / प्रवर्तक कौन हैं कंपनियों और उनके झुकाव।

4. जबकि संपादकीय स्वतंत्रता की गारंटी संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) द्वारा दी गई है, जो मीडिया को स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार देता है, प्रेस परिषद अधिनियम कहता है कि प्रेस परिषद के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों को उनकी स्वतंत्रता बनाए रखने में मदद करें। फिर भी, जैसा कि पहले ही ऊपर कहा जा चुका है, अगर मीडिया संगठन बड़े पैमाने पर कॉरपोरेट संस्थाओं / महासंघों के स्वामित्व में हैं (जो कि 2002 और 2013 के अधिनियमों में अभी भी अपरिभाषित है) और इन कंपनियों के पास एक एजेंडा, राजनीतिक, व्यवसाय या अन्यथा, संपादकीय स्वतंत्रता है समझौता हो जाता। संपादकीय स्वतंत्रता भी उस कंपनी की नीतियों पर निर्भर करेगी जो मीडिया और संपादक के प्रभारी हैं।

एक संस्था केवल उतनी ही प्रभावी होती है जितना कि वह व्यक्ति।

4.8 कानून में संशोधन

[93] https://www.thenewsminute.com/article/jaya-govt-filed-213-defamation-complaints-5-years-here-are-some-strangest-cases-48362

[94] https://www.thebetterindia.com/162334/criminal-defamation-india-news/

[95] https://scroll.in/article/903119/anil-ambanis-defamation-blitz-28-cases-filed-by-reliance-group-in-ahmedabad-courts-this-year

[96] http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/3100.pdfhttp://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/3100.pdf

[97] https://scroll.in/article/877838/who-is-anti-national-the-bastar-journalist-charged-with-sedition-raises-important-questions

राज्य के विज्ञापन वितरण[98] के संबंध में कानून में संशोधन[99], स्पेक्ट्रम आवंटन की प्रक्रिया और मीडिया आउटलेट के लिए करों का उल्लेख यहां किया गया है।

5. नेट तटस्थता (एनएन)

5.1 एनएन से संबंधित कानून

1. भारत में नेट तटस्थता को नियंत्रित करने वाला कोई विशिष्ट कानून, क़ानून या अधिनियम नहीं है। DoT ने 31 जुलाई, 2018 को नेट न्यूट्रैलिटी पर एक नियामक ढांचे को मंजूरी दी, जिसमें यह कहा गया कि 'सरकार नेट न्यूट्रैलिटी के मूल सिद्धांतों और अवधारणाओं के लिए प्रतिबद्ध है यानी बिना किसी भेदभाव के इंटरनेट को सुलभ और सभी के लिए उपलब्ध है।'

इसलिए, इंटरनेट एक्सेस सेवाओं को एक सिद्धांत द्वारा शासित किया जाना चाहिए, जो सामग्री के उपचार में किसी भी प्रकार के भेदभाव, प्रतिबंध या हस्तक्षेप को रोकता है, जिसमें अवरुद्ध करना, अपमानित करना, धीमा करना या तरजीही गति या किसी भी सामग्री को उपचार प्रदान करने जैसी प्रथाएं शामिल हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नेट तटस्थता पर नियामक ढांचा नेट न्यूट्रैलिटी के मूल सिद्धांतों और अवधारणाओं का पालन करता है, नेट न्यूट्रैलिटी पर नीति निर्देश जारी किए गए हैं।[100]

2. वास्तव में 03 मार्च, 2016 को, DoT ने TRAI अधिनियम, 1997 की धारा 11 (1) (ए) के प्रावधानों के अनुसार, शुद्ध तटस्थता के विषय पर अपनी सिफारिशें देने के लिए TRAI से अनुरोध किया। 2 नवंबर, 2017[101], को 'नेट न्यूट्रैलिटी'[102] पर DoT की अपनी सिफारिशें, जिन्हें DoT ने नेट न्यूट्रैलिटी पर अपनी पॉलिसी जारी करते समय स्वीकार कर लिया था। DoT ने निवल तटस्थता से संबंधित क्लॉस को शामिल करके लाइसेंस नियमों में संशोधन किया, जो सेवा प्रदाताओं को इंटरनेट की सामग्री और सेवाओं के खिलाफ भेदभाव करने से रोकता है, तरजीही उच्च गति को अवरुद्ध, थ्रॉटलिंग या अनुदान देकर।

3. 8 फरवरी, 2016 को, TRAI ने अपने नियमों को जारी किया "डेटा सेवाओं, विनियमों, 2016[103] के लिए भेदभावपूर्ण शुल्क पर प्रतिबंध", जो कि, अन्य बातों के साथ, किसी भी सेवा प्रदाता को सामग्री के आधार पर डेटा सेवाओं के लिए भेदभावपूर्ण टैरिफ की पेशकश या चार्ज करने से प्रतिबंधित करता है। यह कहा गया है:

- कोई भी सेवा प्रदाता सामग्री के आधार पर डेटा सेवाओं के लिए भेदभावपूर्ण शुल्कों की पेशकश या शुल्क नहीं लेगा।
- कोई भी सेवा प्रदाता किसी भी व्यक्ति, प्राकृतिक या कानूनी के साथ, किसी भी नाम से, किसी भी व्यवस्था, समझौते या अनुबंध में प्रवेश नहीं करेगा, जिसमें डेटा सेवाओं के लिए भेदभावपूर्ण टैरिफ का प्रभाव होता है या सेवा प्रदाता के उद्देश्य से शुल्क लिया जाता है। इस विनियमन में निषेध का अनुमान लगाना।

5.2 एनएन के साथ काम करने वाले कानून और प्राधिकरण

भारत में, स्पेक्ट्रम के लाइसेंस और आवंटन के मुद्दों को DoT द्वारा निपटाया जाता है जबकि नियामक पहलुओं को TRAI द्वारा निपटाया जाता है। इसलिए, वर्तमान में TRAI के नियम और DoT की नीति अनिवार्य रूप से नेट तटस्थता की अवधारणा को कवर करती है। TRAI दूरसंचार क्षेत्र में एक स्वतंत्र नियामक है, जो मुख्य रूप से टीएसपी और उनकी लाइसेंस शर्तों आदि को नियंत्रित करता है।

5. 3 एनएन की परिभाषा

नेटवर्क तटस्थता को नेटवर्क डिजाइन सिद्धांत के रूप में सबसे अच्छा परिभाषित किया गया है। "नेट तटस्थता" शब्द को इस विचार का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार किया गया था कि "एक अधिकतम उपयोगी सार्वजनिक सूचना नेटवर्क सभी सामग्री, साइटों और प्लेटफार्मों के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहता है"[104]। भारत में आईटी एक्ट साइबर स्पेस को नियंत्रित करता है। 2015 में, TRAI ने नियामक कंसल्टेंसी पेपर में "ओवर-द-टॉप (ओटीटी) सेवाओं के लिए नियामक ढांचा" पर परिभाषित किया, जिसमें बताया गया कि टीएसपी सभी नेट ट्रैफ़िक को एक समान आधार पर व्यवहार करना चाहिए, चाहे इसके प्रकार या सामग्री की उत्पत्ति क्यों न हो। या पैकेट को प्रेषित करने के लिए उपयोग किया जाता है. [105]

5.4 एनएन का कार्यान्वयन

विभिन्न अधिकारी संभवतः भविष्य में विभिन्न तटस्थताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए नेट तटस्थता पर निकट भविष्य में कानून बनाएंगे।

1. जैसा कि ऊपर कहा गया है, नेट तटस्थता को 31 जुलाई, 2018 को जारी नेट न्यूट्रैलिटी द्वारा 2016 के अपने विनियमों के माध्यम से "डेटा सेवाओं, विनियमों, 2016 के लिए भेदभावपूर्ण शुल्क का निषेध" और DoT द्वारा अपने विनियमन द्वारा विनियमित किया जा रहा है।

---

[98] Ibid p. 33
[99] Ibid p.33
[100] http://dot.gov.in/net-neutrality
[101] https://main.trai.gov.in/sites/default/files/PR_No.100of2017.pdf
[102] http://main.trai.gov.in/sites/default/files/Recommendations_NN_2017_11_28.pdf
[103] https://main.trai.gov.in/sites/default/files/Regulation_Data_Service.pdf
[104] http://www.timwu.org/network_neutrality.html
[105] https://main.trai.gov.in/sites/default/files/OTT-CP-27032015.pdf

उक्त विनियामक ढांचे में, डीओटी को नेट तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और प्रवर्तन संस्थान होना है।

वास्तव में, DoT ने यह भी स्पष्ट किया है कि नेट तटस्थता की शर्त का उल्लंघन दूरसंचार ऑपरेटरों को जारी लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा।

नेट तटस्थता इंटरनेट में चार अलग-अलग प्रकार के हितधारकों पर लागू होती है:

(i) किसी भी इंटरनेट सेवा के उपभोक्ता, (ii) टीएसपी या इंटरनेट सेवा प्रदाता / आईएसपी, (iii) ओटीटी सेवा प्रदाता (जो इंटरनेट एक्सेस सेवाएं प्रदान करते हैं जैसे वेबसाइट और अनुप्रयोग), और (iv) सरकार, जो इन खिलाड़ियों के बीच संबंधों को विनियमित और परिभाषित कर सकती है।

नेट तटस्थता से संबंधित पॉलिसी में DoT ने जो अपवाद किए हैं, वे निम्न हैं:

(i) इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) सेवाएं जो महत्वपूर्ण हैं

(ii) विशिष्ट सेवाएँ

इन उपरोक्त शर्तों को अन्य हितधारकों के परामर्श से DoT द्वारा भविष्य में परिभाषित किया जाएगा। DoT ने कहा कि बाद में TRAI उन नियमों पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगा जो सामग्री वितरण नेटवर्क को छूट देते हैं जो गैर-भेदभावपूर्ण उपचार पर प्रतिबंधों से सार्वजनिक इंटरनेट का उपयोग नहीं करते हैं। TRAI के परामर्श से एक समिति दूरसंचार ऑपरेटरों को सेवाओं की गुणवत्ता, नेटवर्क की सुरक्षा, आपातकालीन सेवाओं, अदालतों के आदेशों के कार्यान्वयन और सरकार के निर्देशों को पारदर्शी बनाने के लिए अपनाने का भी आदेश देगी, जब तक कि वे पारदर्शी न हों और उपयोगकर्ताओं पर प्रभाव घोषित न हो ।

भारत के नेट तटस्थता नियम कहते हैं कि दूरसंचार और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को उन समझौतों पर हस्ताक्षर करने से रोक दिया जाना चाहिए जो सामग्री, प्रेषक, प्रोटोकॉल या यहां तक कि उपकरण के आधार पर भेदभावपूर्ण उपचार कर सकते हैं। [106]/[107]

2. उक्त छूटों[108] से एयरटेल और Jio बनाम कनेक्टिविटी प्रदाताओं जैसे बड़े एकीकृत वाहकों को लाभ मिलने की उम्मीद है क्योंकि एकीकृत वाहकों में पहले से ही सामग्री प्लेटफार्मों में मजबूत उपस्थिति है।[109] इस अवलोकन का निकट भविष्य में मूल्यांकन करना होगा। नेट तटस्थता नीति के उल्लंघन की खबरें आई हैं[110]। कुछ टेलीकॉम ऑपरेटरों द्वारा शिकायतें वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स के प्रॉक्सी और कंसंट्रेशन को ब्लॉक करने की बताती हैं। वर्तमान में, नेट तटस्थता को विनियमित करने वाले कानून इस तथ्य के मद्देनजर पर्याप्त प्रतीत होते हैं कि अवधारणा भारत के लिए अपेक्षाकृत नई है।

हालाँकि, नेट तटस्थता की नीतियों को भविष्य में संशोधनों की आवश्यकता हो सकती है यदि विधान / विनियम बाजार में कई कंपनियों / खिलाड़ियों के अस्तित्व में परिणाम नहीं करते हैं विशेष रूप से दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में। यदि बाजार में काम करने वाली दूरसंचार / प्रसारण कंपनियों की संख्या कम हो जाती है, तो उस घटना में, एकाधिकार और वृद्धि पर एकाग्रता के साथ, शुद्ध तटस्थता सहन नहीं होगी।

निष्कर्ष

वर्तमान में मीडिया एकाग्रता पर विधान में एकरूपता, स्थिरता और प्रभावशीलता का अभाव है। चूंकि यह केवल "प्रतियोगिता" के संदर्भ में समझा जाता है, इसलिए यह मीडिया के एकाधिकार को रोकने के लिए अपर्याप्त / अक्षम होगा। चूंकि मीडिया एक अनोखी भूमिका निभाता है और विचारों और विचारों को आकार देने में एक बड़ा प्रभाव रखता है, जैसा कि TRAI द्वारा बताया गया है, मीडिया को बाजार में प्रचलित सामान्य वस्तु नहीं माना जाना चाहिए। इसलिए, मीडिया की बहुलता को बनाए रखने के किसी भी प्रयास को प्रतियोगिता से संबंधित कानून द्वारा निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए। अगर मीडिया एकाग्रता को रोका जाना है, तो इससे संबंधित विशिष्ट कानूनों को कानून बनाना होगा।

इसके अनुसार, ऐसे विधानों के प्रभावी होने के लिए मीडिया एकाग्रता से संबंधित विधानों से संबंधित एक ही प्राधिकरण होना चाहिए।

कुछ अधिनियमों के प्रावधानों की भी समीक्षा करने की आवश्यकता होगी जैसे कि कंपनी अधिनियम, 2013, ताकि कंपनियों / उद्यम / समूहों को वास्तविक लेन-देन / प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए जटिल लेनदेन में प्रवेश करने से रोका जा सके और किसी कंपनी के एक बार प्रवेश करने पर उसे प्रभावित और नियंत्रित किया जा सके। एक विलय में, या किसी अन्य संस्था का अधिग्रहण करता है। इस पत्र में बताए गए कारणों के लिए मीडिया क्षेत्र में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

[106] https://economictimes.indiatimes.com/articleshow/65296830.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

[107] https://www.business-standard.com/article/companies/dot-amends-licences-of-telcos-to-incorporate-net-neutrality-rules-118080700357_1.html

[108] https://www.bloombergquint.com/law-and-policy/telecom-regulator-releases-suggestions-to-protect-net-neutrality

[109] https://economictimes.indiatimes.com/articleshow/65296830.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

[110] https://internetfreedom.in/more-than-100-people-report-violations-of-net-neutrality-all-over-india-we-need-enforcement-action/

स्रोत

1. KPMG (2018). Media Ecosystems: The walls fall down. Retrieved from: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/in/pdf/2018/09/Media-ecosystems-The-walls-fall-down.pdf
2. Agarwal Anushi (2018). Mapping the Power of Major Media Companies in India. Retrieved from: http://www.academia.edu/37877812/Mapping_the_Power_of_Major_Media_Companies_in_India
3. AIR 1950 SC 594
4. AIR 1950 SC 129
5. AIR 1962 SC 305
6. AIR 1973 SC 106
7. AIR 1995 SC 2438
8. AIR 1975 SC 865
9. 2003 (1) SC 591
10. 1995(2) SCC 161
11. Press Information Bureau (2012). National Competency Policy. Retrieved from: http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=79466
12. TRAI (2013), Recommendations on Monopoly/Market dominance in cable TV service. Retrieved from: https://main.trai.gov.in/sites/default/files/Recommendations_Cable_monopoly_final_261113%20(1).pdf
13. Television Post (2018). MIB on cross-media restrictions, cable monopoly, and new DTH guidelines. Retrieved from: https://www.televisionpost.com/mib-on-cross-media-restrictions-cable-monopoly-and-new-dth-guidelines/
14. GOI (2002). The Competition Act,2002. Retrieved from: https://www.cci.gov.in/sites/default/files/cci_pdf/competitionact2012.pdf
15. GOI (2001). Guidelines for Obtaining License for Providing direct to Home Broadcasting Service in India. Retrieved from: https://mib.gov.in/sites/default/files/GuidelinesforDTHServiceDated15.3.2001.pdf
16. GOI (2007). Guidelines for Obtaining License for Providing Direct to Home Broadcasting Service in India. Retrieved from: https://mib.gov.in/sites/default/files/Detailsguidlinesupdated6.11.2007.pdf
17. GOI (2011). Policy Guidelines on Expansion of FM Radio Broadcasting Services Through Private Agencies (Phase-III). Retrieved from: https://www.broadcastseva.gov.in/fm_Lading_Page/FM_Phase_III_Policy.pdf
18. 2019(2) SCC 104
19. TRAI (2017). The Telecommunication (Broadcasting and cable) Services Interconnection (Addressable Systems) Regulations, 2017. Retrieved from: https://main.trai.gov.in/sites/default/files/Interconnection_Regulation_03_mar_2917.pdf
20. OECD (2013). Competition Issues in Television and Broadcasting. Retrieved from: http://www.oecd.org/daf/competition/TV-and-broadcasting2013.pdf
21. Medianama (2014). How Reliance Industries acquired Network18: A detailed timeline of events. Retrieved from: https://www.medianama.com/2014/05/223-how-reliance-industries-acquired-network18-a-detailed-timeline-of-events/
22. Santikari Soumya (2016). Year-end special: Top six media and entertainment deals of 2016. Retrieved from:https://economictimes.indiatimes.com/industry/media/entertainment/media/et-year-end-special-top- six-media-and-entertainment-deals-of-2016/articleshow/55807372.cms
23. India television (2019). MIB gives Licenses to 5 New Channels. Retrieved from: http://www.indiantelevision.com/regulators/ib-ministry/mib-gives-licences-to-5-new-channels-190119
24. GOI, Office of Registrar of Newspapers for India. Retrieved from: http://rni.nic.in/general/organisation-setup.aspx
25. ASCI (2009). Study on Cross Media Ownership in India. Retrieved from: https://cablequest.org/pdfs/i_b/ASCI%20Cross%20Media%20ownership%20in%20India%202009.pdf
26. TRAI (2014). Information note to the press (Press Release No. 51/2014). Retrieved from: https://main.trai.gov.in/sites/default/files/Press%20Release%20dated%2012th%20Aug%2014.pdf
27. TRAI (2014). Recommendations on Issues Relating to Media Ownership. Retrieved from:https://main.trai.gov.in/sites/default/files/Recommendations_on_Media_Ownership.pdf
28. 2019 (2) SCC 521
29. GOI (2017). Consolidated FDI Policy Circular of 2017. Retrieved from: https://dipp.gov.in/sites/default/files/CFPC_2017_FINAL_RELEASED_28.8.17.pdf
30. GOI (2005). Guidelines for Publication of Indian Editions of Foreign Technical/Scientific/Speciality Magazines/Journals/Periodicals; and Foreign investment in Indian Entities Publishing Scientific/Technical/Speciality Magazines/Journals/Periodicals. Retrieved from:https://mib.gov.in/sites/default/files/Guidelines_for_Publication_of_Indian_edition_of_Specialty_Magazines.pdf
31. GOI. Ministry of Information and Broadcasting. Retrieved from: https://mib.gov.in./
32. GOI. Prasar Bharti. Retrieved from: http://prasarbharati.gov.in/
33. GOI (2002). Policy Guidelines for setting up Community Radio Stations in India. Retrieved from: http://wdfindia.org/CRBGUIDELINES041206.pdf
34. TRAI (1997). Arrangement of Sections. Retrieved from: https://main.trai.gov.in/sites/default/files/The_TRAI_Act_1997.pdf
35. Augustine Peter (2008). Competition Act, 2002: Anti-Competitive Agreements Including Cartels. Retrieved from: https://www.cci.gov.in/sites/default/files/presentation_document/anti_peter_20090213111438.pdf?download=1
36. CCOI (2002). Provisions Relating to Abuse of Dominance. Retrieved from: https://www.cci.gov.in/sites/default/files/advocacy_booklet_document/AOD.pdf
37. CCOI (2002). Provisions Relating to Combinations. Retrieved from: https://www.cci.gov.in/sites/default/files/advocacy_booklet_document/combination.pdf
38. GOI (2002). The Competition Act. Retrieved from: https://www.cci.gov.in/sites/default/files/cci_pdf/competitionact2012.pdf
39. TRAI. Annual Reports. Retrieved from: https://main.trai.gov.in/about-us/annual-reports
40. CCOI. Annual Reports. Retrieved from: https://www.cci.gov.in/annual-reports
41. http://www.cuts-ccier.org/IICA/pdf/Country_Paper_India.pdf
42. The Hoot (2014). Competition Vs Plurality. Retrieved from: http://asu.thehoot.org/media-watch/law-and-policy/competition-vs-plurality-7718
43. The Caravan (2019). Data Plans: How government Decisions are helping Reliance Jio Monopolise the telecom Sector. Retrieved from:

https://caravanmagazine.in/reportage/government-helping-reliance-jio-monopolise-telecom
44. Kumar Samarika (2019). Five reasons why media monopolies flourish in India. Retrieved from: https://scroll.in/article/694139/five-reasons-why-media-monopolies-flourish-in-india
45. GOI. Annual Returns. Retrieved From: http://www.mca.gov.in/SearchableActs/Section92.htm
46. GOI (2013). The Companies Act. Retrieved from: http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/CompaniesAct2013.pdf
47. SEBI (2015). Circular. Retrieved from: https://www.nseindia.com/content/equities/SEBI_Circ_09092015.pdf
48. SEBI Listing Obligations and Disclosure Requirements, 2018. EY. Retrieved from: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-sebi-listing-obligations-and-disclosure-requirements-amendment-regulations-2018/$File/EY-sebi-listing-obligations-and-disclosure-requirements-amendment-regulations-2018.pdf
49. GOI (2011). Policy Guidelines for Downliking of Television Channels. Retrieved from https://mib.gov.in/sites/default/files/Downlinking_Guidelines05.12.11.pdf
50. GOI (2011). Policy Guidelines for Uplinking of Television Channels from India. Retrieved from: https://mib.gov.in/sites/default/files/FinalUplinkingGuidelines05.12.2011.pdf
51. GOI. Form Four. Retrieved from: http://rni.nic.in/proforma/pdf_file/form4.pdf
52. The Hoot (2012). Media ownership In India: An Overview. Retrieved from: http://asu.thehoot.org/resources/media-ownership/media-ownership-in-india-an-overview-6048
53. NBSA (2014). Guidelines for Election Broadcasts. Retrieved from: http://www.nbanewdelhi.com/assets/uploads/pdf/12_Guidelines_for_Election_Broadcasts_3_3_14_E.pdf
54. GOI (2018). Guidelines for obtaining data from MCA. Retrieved from:http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/GuidelinesMCA_final_12022018.pdf
55. GOI (2018) .2017-2018 Annual Report. Retrieved from: http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/AnnualReport2017_18_19022018.pdf
56. GOI. Annual reports. Retrieved from: http://dot.gov.in/reports-statistic/2471
57. GOI (2005). The Gazette of India. Retrieved from: https://rti.gov.in/rti-act.pdf
58. Money Control (2018). Media & Entertainment industry – Key tax issues and expectations from Budget 2018. Retrieved from: https://www.moneycontrol.com/news/business/media-entertainment-industry-key-tax-issues-and-expectations-from-budget-2018-2489881.htm
59. Equity Sector (2019). Media Sector Analysis Report. Retrieved from: https://www.equitymaster.com/research-it/sector-info/media/Media-Sector-Analysis-Report.asp
60. TRAI (2018). Recommendations on Ease of Doing Business in Broadcasting Sector. Retrieved from https://main.trai.gov.in/sites/default/files/Recommendation_EODB_26022018.pdf
61. RMBiz (2015). How did New Entrants to the Radio Industry Fare? Find out. Retrieved from: http://www.radioandmusic.com/biz/radio/private-fm-stations/151004-how-did-new-entrants-radio-industry-fare
62. A. Raja Versus Subramanian Swamy 2012 (9) SCC 257
63. Cuts International (2012). Verdict of Supreme Court on 2G Spectrum Allocations – Pre-Consultation Comments (Preliminary) of CUTS to TRAI. Retrieved from: https://main.trai.gov.in/sites/default/files/CUTS_plimanry.pdf
64. GOI (2018). National Frequency Allocation Plan-2018. Retrieved from: http://wpc.dot.gov.in/WriteReadData/userfiles/NFAP%202018.pdf
65. Ravi Shamika and Darell. M. West (2015). Spectrum Policy in India. Retrieved from: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2017/05/spectrum-policy-in-india8515.pdf
66. Live Mint (2018). DoT seen allocating spectrum in E, V bands without an auction. Retrieved from https://www.livemint.com/Industry/TYhSyudzRVf69px5KeKuwN/DoT-seen-allocating-spectrum-in-E-V-bands-without-an-auctio.html
67. The Wire (2018). Modi Govt May Allocate Valuable Spectrum on First Come, First Serve Basis. Retrieved from: https://thewire.in/business/modi-govt-to-allocate-valuable-spectrum-on-first-come-first-serve-basis
68. GOI. Bureau of Outreach and Communication. Retrieved from: http://www.davp.nic.in/
69. GOI (2017). Directorate of Advertising and Visual publicity. Retrieved from: http://davp.nic.in/writereaddata/announce/TV%20Amendment_31_8_2017.pdf
70. GOI. Bureau of Outreach and Communication. Retrieved from: http://www.davp.nic.in/Newspaper_Advertisement_Policy.htmls
71. GOI (2016). Directorate of Advertising and Visual publicity. Retrieved from http://davp.nic.in/writereaddata/announce/Adv6131282016.pdf
72. Industrial Economist (2015). Small is No Longer Beautiful. Retrieved from: http://www.industrialeconomist.com/page.php?page=80&cid=1053
73. NBA Annual Report 2016-2017. Retrieved from: http://www.nbanewdelhi.com/assets/uploads/pdf/10TH_AR_2016-17.pdf
74. NBA (2017). 10 Annual Report. Retrieved from: https://theprint.in/india/governance/modi-govt-hikes-ad-rates-for-private-channels-looks-to-boost-tv-presence-ahead-of-polls/183351/
75. AIR 2015 SC 1523
76. Sathe Gopal (2018). The Supreme Court Struck Down Section 66A of the IT Act in 2015, Why Are Cops Still Using It to Make Arrests? Retrieved from: https://www.huffingtonpost.in/2018/10/15/the-supreme-court-struck-down-section-66a-of-the-it-act-in-2015-why-are-cops-still-using-it-to-make-arrests_a_23561703/
77. Bahri Charu (2018). Police using Section 66A of IT Act to Make Arrests Despite SC's Ruling https://www.business-standard.com/article/current-affairs/police-using-section-66a-of-it-act-to-make-arrests-despite-sc-s-ruling-118120300067_1.html
78. Muralidharan Sukumar (2013). Quashing Dissent: Where National Security and Commercial Media Converge. https://www.epw.in/journal/2013/09/web-exclusives/quashing-dissent-where-national-security-and-commercial-media
79. 2016 (7) SCC 221
80. The News Minute (2016). Jaya Government filed 213 defamation complaints in 5 years: here are some of the Strangest Cases. Retrieved from:https://www.thenewsminute.com/article/jaya-govt-filed-213-defamation-complaints-5-years-here-are-some-strangest-cases-48362
81. Wangchuk, Norbun Rinchen: Criminal Defamation: Relic of The Raj, This Act Harasses More Than it Helps. retrieved from: https://www.thebetterindia.com/162334/criminal-defamation-india-news/
82. Vijayta Lalwani (2018). Anil Ambani's defamation blitz: 28 cases filed by Reliance Group in Ahmedabad courts this year. Retrieved from: https://scroll.in/article/903119/anil-

ambanis-defamation-blitz-28-cases-filed-by-reliance-group-in-ahmedabad-courts-this-year

83. Malini Subramaniam (2018). Who is anti-national? Sedition charge against Bastar reporter for Facebook post raises key questions. Retrieved from: https://scroll.in/article/877838/who-is-anti-national-the-bastar-journalist-charged-with-sedition-raises-important-questions
84. GOI (2018). Net Neutrality. Retrieved from: http://dot.gov.in/net-neutrality
85. TRAI (2016). Prohibition of Discriminatory Tariffs for Data Services Regulations, 2016. Retrieved from: https://main.trai.gov.in/sites/default/files/Regulation_Data_Service.pdf
86. Tim Wu (2003). Network Neutrality FAQ. Retrieved from: http://www.timwu.org/network_neutrality.html
87. TRAI (2015). Consultation Paper On Regulatory Framework for Over-the-top (OTT) services. Retrieved from: https://main.trai.gov.in/sites/default/files/OTT-CP-27032015.pdf
88. TRAI (2017). Recommendations On Net Neutrality. Retrieved from: https://main.trai.gov.in/sites/default/files/Recommendations_NN_2017_11_28.pdf
89. TRAI (2017). TRAI Releases recommendations on Net Neutrality. Retrieved from: https://main.trai.gov.in/sites/default/files/PR_No.100of2017.pdf
90. Parbat Kalyan (2018). DoT Amends License Conditions To Incorporate Net Neutrality Rules. Retrieved from: https://economictimes.indiatimes.com/industry/telecom/telecom-news/dot-amends-license-conditions-to-incorporate-net-neutrality-rules/articleshow/65296830.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst
91. Rathee Kiran (2018). DoT amends Licenses of Telcos to Incorporate Net Neutrality Rules. Retrieved from: https://www.business-standard.com/article/companies/dot-amends-licences-of-telcos-to-incorporate-net-neutrality-rules-118080700357_1.html
92. The Economic Times (2018). Telecom Commission Clears New Telecom Policy, Backs Net Neutrality. Retrieved from: http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/64947609.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppsthttps://www.bloombergquint.com/law-and-policy/telecom-regulator-releases-suggestions-to-protect-net-neutrality
93. Internet Freedom Foundation (2019). More than 100 people report violations of net neutrality all over India. We need enforcement action. #SaveTheInternet. Retrieved from: https://internetfreedom.in/more-than-100-people-report-violations-of-net-neutrality-all-over-india-we-need-enforcement-action/